Follow Us :- @newsroutine @newsroutine @newsroutine @newsroutine

RNI NO. CHHHIN/2022/83778

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

E-mail: newsroutine6@gmail.com

✦ वर्ष-05 ✦अंक-05 ✦ मई-2026 ✦ सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्रकाशित ✦पृष्ठ-32 ✦ मूल्य-35 रुपये

सुवेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री

सुशासन तिहार में सीएम ने जीत लिया लोगों का दिल

जशपुर की नाशपाती से बढ़ रही किसानों की आमदनी, 3,500 से अधिक कृषक जुड़े फल उत्पादन से

बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नेतानार ग्राम में जनसुविधाओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण की पहल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बस्तर की इमली का स्वाद चखा और उसकी मिठास की सराहना की।

जशपुर. जशपुर की नाशपाती से बढ़ रही किसानों की आमदनी, 3,500 से अधिक कृषक जुड़े फल उत्पादन से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जशपुर जिले के किसान नाशपाती की खेती के माध्यम से उल्लेखनीय आय अर्जित कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। प्राकृतिक रूप से अनुकूल जलवायु और उद्यानिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन के कारण जशपुर आज राज्य के प्रमुख नाशपाती उत्पादक जिलों में शामिल हो चुका है। जशपुर जिले में लगभग 3,500 से अधिक किसान करीब 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में नाशपाती की खेती कर रहे हैं। जिले में प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख 75 हजार क्विंटल नाशपाती का उत्पादन हो रहा है। इससे हजारों कृषक परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और जिले की पहचान फल उत्पादन के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रही है। जशपुर की नाशपाती स्वाद, गुणवत्ता और आकर्षक आकार के कारण देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से पसंद की जाती है। जिले के सन्ना, पंडरापाठ, कंवई, महुआ, सोनक्यारी, मनोरा, धवईपाई और गीधा जैसे क्षेत्रों से नाशपाती की खेप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा सहित अन्य राज्यों में भेजी जाती है। फल को सावधानीपूर्वक कैरेट में पैक कर बाजारों तक पहुंचाया जाता है।

नाशपाती की खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। एक एकड़ क्षेत्र से किसानों को औसतन 1 लाख से 1.50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और किसान आधुनिक उद्यानिकी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं।

उद्यानिकी विभाग तथा नाबार्ड के सहयोग से किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, पौधरोपण, बागवानी प्रबंधन और विपणन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत नाशपाती क्षेत्र विस्तार योजना संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को अनुदान एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से जशपुर जिले में उद्यानिकी आधारित कृषि को नई दिशा मिली है। नाशपाती की खेती न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि जशपुर को राज्य के एक उभरते हुए फल उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है।

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

RNI NO. CHHHIN/2022/83778
E-mail: newsroutine6@gmail.com

सारंगढ़-बिलाईगढ़ से प्रकाशित

प्रधान संपादक
गुलाब दास दीवान

सह- संपादक
जयदास मानिकपुरी

कानूनी सलाहकार
जवाहर पड़वार
इंदुभूषण पड़वार

प्रधान कार्यालय
न्यूज रूटीन
बाजार काम्पलेक्स, नगर पंचायत
पवनी, जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़
पिन. नं. 493338
मो.नं. 9294743139

रायपुर कार्यालय
सह- संपादक-**जयदास मानिकपुरी**
देव मेडिकल स्टोर के पास,हाउस नम्बर
55वार्ड नंबर- 04, साई राम चौक,
गोवर्धन नगर भनपुरी, रायपुर
मो. न. 62611,55546 छत्तीसगढ़- 492001

न्यूज रूटीन में प्रकाशित आलेखों से संपादक, प्रकाशक, मुदक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला रहेगा। सभी पद पूर्णतः मानसेवी व अवैतनिक। समाचार स्त्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्रीः इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से सादर साभार।
संपादक- गुलाब दास दीवान

वर्ष-05 | अंक- 05 | मई-2026

इस अंक में

2. एमएसपी पर राजनीति तो हमेशा होती है
3. सुवेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री
4. बंगाल विजय में अहम रही संघ की भूमिका
6. विपक्ष के सामने अस्तित्व की चुनौती, बंगाल जैसा रहा हाल तो बंद हो जाएंगी राजनीति की खिड़कियां
7. कोलकाता के मंच पर जब ठहर गया वक्त: PM मोदी ने आखिर क्यों छुए इस 98 वर्षीय बुजुर्ग के पैर ?
8. असम में BJP ने लगाई जीत की हैट्रिक, सियासी वनवास खत्म नहीं कर पाई कांग्रेस
9. थलपति विजय ने 14 साल की बच्ची की अपील पर अपनी VIP कुर्सी के पीछे से सफेद तौलिया हटाया
10. पुडुचेरी में फिर से रंगासामी की सरकार
11. 19 हजार के लिए कंकाल निकाला, अब मिले 15 लाख
12. आम जनता से शालीनता से पेश आएं अधिकारी
13. सुशासन तिहार में सीएम ने जीत लिया लोगों का दिल
17. "गब्बर फाइल्स -अब सच दबेगा नहीं... दर्ज होगा" : अकील
18. जल जीवन मिशन में 15.50 लाख का फर्जीवाड़ा: परसदा

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- **गुलाब दास दीवान,** द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित।
RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139

एमएसपी पर राजनीति तो हमेशा होती है

केंद्र सरकार हर साल खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। हर साल फसलों का समर्थन मूल्य कुछ न कुछ बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि फसलों का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार अपनी मर्जी से बढ़ा देती है। देश में हर साल फसलों का समर्थन मूल्य एक तय प्रक्रिया के मुताबिक बढ़ाया जाता है।ऐसा भी नहीं है कि यह प्रक्रिया कांग्रेस सरकार के समय कुछ थी और मोदी सरकार के समय कुछ और हो गई है।जिस तय प्रक्रिया का माध्यम से कांग्रेस के समय फसलों की एमएसपी तय होती थी, उसी तय प्रक्रिया के मुताबिक आज भी एमएसपी तय होती है। जब भी केंद्र सरकार धान का एमएसपी बढ़ाती है तो छत्तीसगढ़ में उसे लेकर राजनीति हमेशा होती रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो जब भी केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करती है तो राज्य में जो विपक्ष हो या सत्ता मे हो राजनीति जरूर होती है।चुनावी राजनीति में राज्य में किसानों को बोटबैंक एक बड़ा वोट बैंक है, इसलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष उनमें खुद को किसान हितैषी बताने की होड़ सी लगी रहती है।वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष में है और सरकार भाजपा की है तो केंद्र सरकार ने जैसे ही एमएसपी की घोषणा कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी।केंद्र सरकार ने धान की समर्थन मूल्य ७२ रूपए बढ़ाया है कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा कहा है तो धनेंद्र साहू ने इसे मामूली वृध्दि बताया है।इसे किसानों के साथ अन्याय कहा है।उनका कहना है कि खेती की लागत बढ़ती जा रही है।ऐसे में मामूली बढ़ोतरी किसानों के घाव पर मरहम नहीं बल्कि मजाक है। कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू याद कर रहे हैं और जनता को याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने २५०० क्विंटल के अतिरिक्त जब जब केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया तो तब कांग्रेस सरकार ने समर्थन मूल्य की राशि जोड़कर किसानों को भुगतान किया था। यानी वह बता रहे हैं कि उनके समय में किसानों को समर्थन मूल्य जोड़कर भुगतान किया गया था यानी २५०० से ज्यादा भुगतान किया गया था। यह सच तो है लेकिन पूरा सच नहीं है क्योंकि कांग्रेस के समय पूरे पांच साल २५०० और हर साल का समर्थन मूल्य जोड़कर भुगतान नहीं किया गया था।एक दो साल ही ऐसा किया गया था। तीन चार साल तो कांग्रेस सरकार भी यही कहती थी किसानों को सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं इसलिए समर्थन मूल्य जोड़कर देने की जरूरत नहीं है। अपने समय में तो कांग्रेस किसानों को पांच साल २५०० से ज्यादा पैसा नहीं दिया लेकिन वह अब जब केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य ७२ रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है तो धनेंद्र साहू मांग कर रहे हैं कि भाजपा सरकार ने किसानों को धान का मूल्य ३१०० रुपए देने की घोषणा की है तो उसे इस साल किसानों को ३१०० और ७२ रुपए इस साल का समर्थन मूल्य और पिछले साल का समर्थन मूल्य जोड़कर किसानों को ३३५८ रुपए दिया जाना चाहिए।कांग्रेस ने साय सरकार से पिछली बार भी मांग की थी कि राज्य के किसानों को ३१०० मे समर्थन मूल्य जोड़कर भुगतान किया जाए। सीएम साय जानते हैं कि कांग्रेस नेता कांग्रेस को किसान हितैषी साबित करने के लिए इस बार भी ऐसी मांग करेंगे। इसलिए सीएम साय ने केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य की घोषणा करने के साथ ही यह साफ कर दिया था कि राज्य में किसानों से ३१०० रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाती है।वर्तमान में सामान्य धान २३६९ रुपए,ग्रेड ए २३८९ की दर से खरीदा जाता है।इसके बाद अंतर की राशि किसानों को एक साथ दी जाती है।इस साल केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य ७२ रुपए बढ़ाया है तो अब किसानों से सामान्य धान २४४१ रुपए और ए ग्रेड धान २४६१ रुपए की दर से खरीदा जाएगा।चूंकि राज्य सरकार किसानों से ३१०० रुपए में धान खरीद रही है इसलिए राज्य सरकार किसानों को अंतर की राशि में ७२ रुपए की कटौती करके किसानों को भुगतान करेगी। यानी किसानों को तो प्रति क्विंटल ३१०० रुपए मिलेगा,अंतर की राशि किसानों को कम मिलेगी। ऐसा कांग्रेस सरकार ने कई साल किया है अब साय सरकार भी वही कर रही है। कांग्रेस के समय यह सही था तो आज भी सही माना जाएगा।जहां तक किसान हितैषी होने का सवाल है किसान जानते हैं कि कौन सही में किसान हितैषी है।

गुलाब दास दीवान

सुवेंदु बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री

न्यूज रुटीन @ **कोलकाता**

सुवेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में BJP के पहले मुख्यमंत्री बन गए। सुवेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को झुककर प्रणाम किया। सुवेंदु के साथ 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, क्षुदीराम टूडू और निषिथ प्रमाणिक शामिल रहे।

कार्यक्रम में PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। NDA और BJP शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे।

PM रोड शो करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे, मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाया और पैर छुए। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से घुटनों के बल झुककर बंगाल की जनता को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने ग्राउंड की एंट्री से मंच तक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ समिक भट्टाचार्य और सुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। बंगाली कैलेंडर के मुताबिक पोचिसे बोइशाख के दिन (9 मई) गुरुदेव की 165वीं जयंती है। पीएम ने मंच पर रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। बंगाली कैलेंडर के मुताबिक पोचिसे बोइशाख के दिन (9 मई) गुरुदेव की 165वीं जयंती है। पीएम ने भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए। 1952 के कश्मीर आंदोलन के दौरान माखनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तिरंगा फहराने के लिए गए थे।

पीएम ने भाजपा कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए। 1952 के कश्मीर आंदोलन के दौरान माखनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तिरंगा फहराने के लिए गए थे।

समारोह के आखिर में एक पल ऐसा भी आया, जहां पीएम मोदी ने मंच से परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को धन्यवाद दिया। वे मंच पर घुटनों के बल बैठे और जनता को प्रणाम किया। समारोह के आखिर में एक पल ऐसा भी आया, जहां पीएम मोदी ने मंच से परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों को धन्यवाद दिया। वे मंच पर घुटनों के बल बैठे और जनता को प्रणाम किया। शपथ ग्रहण के लिए तैयार मंच के बैकग्राउंड का थीम दुर्गा पूजा और कालीघाट काली मंदिर पर तैयार किया गया था। शपथ ग्रहण में भाजपा-NDA शासित राज्यों के CM शामिल हुए। बिहार CM सम्राट चौधरी, उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली CM रेखा गुप्ता, सिक्किम CM प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू और हरियाणा CM नायब सैनी ने साथ में फोटो खिंचवाई।

शपथ ग्रहण में भाजपा-NDA शासित राज्यों के CM शामिल हुए। बिहार CM सम्राट चौधरी, उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली CM रेखा गुप्ता, सिक्किम CM प्रेम सिंह तमांग, अरुणाचल प्रदेश CM पेमा खांडू और हरियाणा CM नायब सैनी ने साथ में फोटो खिंचवाई।

PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि, राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल, निसिथ प्रमाणिक, क्षुदिराम टुडू के साथ फोटो खिंचवाई।

सुवेंदु की मां बोलीं- बेटा आरजीकर रेप विक्टिम के परिवार को न्याय दिलाए- सुवेंदु के शपथ लेने के बाद उनकी मां गायत्री अधिकारी ने कहा- 'बेटे पर गर्व है। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा आरजी कर मेडिकल कॉलेज की रेप विक्टिम के परिवार को न्याय दिलाए। वहीं, शनिवार को शपथ लेने के तुरंत बाद सुवेंदु ने राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्ध नाथ गुप्ता और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों ने बताया कि शुभेंदु ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि टीएमसी की योजनाएं चलती रहें।

बंगाल विजय में अहम रही संघ की भूमिका

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत में वैसे तो कई कारक रहे हैं, लेकिन एक अहम बिंदु RSS का है। बीजेपी के लिए आरएसएस ने पिछले एक दशक में शांत तरीके से जमीन पर उतरकर काम किया। संगठन में विस्तार की पुरजोर कोशिशें कीं। उसी का नतीजा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई। बीजेपी ने बंगाल के इस बार के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा मुखरता के साथ उठाया था लेकिन ऐसा नहीं हैं, कि ये बीजेपी के लिए कोई नया मुद्दा नहीं बल्कि यहां हिंदू पहचान की राजनीति का इतिहास एक सदी पुराना है। इसके बावजूद आरएसएस और बीजेपी के पूर्ववर्ती संगठन यानी जनसंघ बंगाल में अपनी जड़े जमाने में कामयाब नहीं हो पाया।

बंगाल में लंबा रहा है बीजेपी का संघर्ष

साल 1951 के बंगाल चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 9 विधानसभा सीटें जीती थीं, और 12.57 वोट प्रतिशत का वोट भी हासिल किया था लेकिन उसके बाद यहां से जनसंघ का नामोनिशान मिटता चला गया। इसके बाद जनसंघ का स्वरूप बदला और वो भारतीय जनता पार्टी बन गई। यह लंबा सूखा 2014 में तब समाप्त हुआ, जब बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी पहली विधानसभा सीट जीती। बीजेपी ने साल 2016 में 3, 2021 में 77 सीटें जीती थीं। वह मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी। इस बार के चुनाव में 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत के साथ सरकार बना ली। वरिष्ठ आरएसएस पदाधिकारियों ने बताया कि चुनावी लिहाज से निर्णायक मोड़ 2021 के विधानसभा चुनाव में आयास क्योंकि RSS को यह समझ आ गया था कि अब ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी लड़ाई जीती जा सकती है। पिछले दो वर्षों में संघ ने भाजपा के जमीनी स्तर के तंत्र में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए अन्य राज्यों से 2,000 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को जुटाया था।

संघ ने जमीन पर उतारे थे कार्यकर्ता

ये कार्यकर्ता संघ और पार्टी के कैडर से लिए गए थे। इन कार्यकर्ताओं के सभी खर्चों का वहन पार्टी द्वारा किया गया था और उन्हें एक ही लक्ष्य दिया गया था।

जमीन स्तर पर गांवों, बस्तियों विशिष्ट समुदायों के बीच काम करने के लिए आरएसएस ने पूरी ताकत झोंकी थी। संघ की भूमिका बीजेपी की राजनीतिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाली सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ बनाने की थी।

2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बंगाल में काफी बड़ा झटका लगा था। इसका काफी हद तक कारण ये माना गया था, कि संघ और बीजेपी के बीच किसी भी तरह का समन्वय स्थापित न हो पाना था।। तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में यह संकेत दिया था कि पार्टी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। उनके इस बयान के बाद आरएसएस ने कथित तौर पर अपनी सक्रियता जमीन पर काफी कम कर दी थी।

इस बार के चुनाव में बेहतर था समन्वय

आरएसएस की मध्य बंगाल इकाई के एक पदाधिकारी ने इस बार के चुनाव को लेकर कहा, "लगातार समन्वय बना रहा। बीजेपी कार्यकर्ता राजनीतिक लड़ाई में सबसे आगे थे, हमारे कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को निडर होकर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बता दें कि राज्य में आरएसएस की संगठनात्मक संरचना उत्तर, मध्य और दक्षिण बंगाल के तीन क्षेत्रों में विभाजित है। राज्य के बाहर से आए 2,000 कार्यकर्ता बारी-बारी से काम करते थे जिनकी न्यूनतम तैनाती तीन महीने की होती थी। 150 से अधिक वरिष्ठ नेता, अन्य राज्यों के विधायक और चुनाव प्रबंधन के अनुभवी

लोग भी लगभग दो वर्षों तक राज्य में डेरा डाले रहे। इन नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में कार्य किया और उनकी भूमिका पारंपरिक चुनाव प्रचार से कहीं अधिक व्यापक थी।

भय के बीच कार्यकर्ताओं ने किया काम

एक बीजेपी नेता ने कहा, "कई जगहों पर तो हमारे आरएसएस-भाजपा कार्यकर्ता भी डरे हुए थे और कई जगहों पर उन्होंने शिकायत की कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें धमकाया है। डर के मारे हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने काम करना भी बंद कर दिया, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि चिंता न करें। हमने उन्हें टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़पों से बचने और घर-घर जाकर संपर्क साधने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया।"जाति, समुदाय, महिला और छात्र समूहों के साथ-साथ शिक्षक और पेशेवर नेटवर्क में तैनात इन कार्यकर्ताओं ने 15-20 लोगों की अनेकों सभाएं कीं। इनमेंमें बंगाली गौरव, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले और सांप्रदायिक विभाजन जैसे भावनात्मक मुद्दों पर सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चर्चा बिंदु शामिल थे।

सुनील बंसल का डेटा मैनेंजमेंट

जमीनी स्तर की ताकत के अलावा, बीजेपी-आरएसएस ने ऐसी नियुक्तियां भी कीं, जिनसे अंततः अच्छे परिणाम मिले। 2016 के चुनावों में भूपेंद्र यादव और कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ी सत्ता में थी। 2021 तक पार्टी ने अपने संयुक्त महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश और राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन को तैनात कर दिया था। शिव प्रकाश ने आरएसएस की तर्ज पर लगभग पांच साल जमीनी स्तर पर काम किया। बंगाल के प्रभारी वर्तमान भाजपा महासचिव सुनील बंसल ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित मॉडल को और बारीकी से लागू किया। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने बंगाल चुनाव में 6 महीने बिताए थे। उन्होंने बताया कि सुनील बंसल और पार्टी द्वारा इस चुनाव में डेटा-आधारित सटीकता के साथ किए गए कार्य की सराहना की।उन्होंने कहा, "डेटा के मामले में रिसर्च इतनी गहरी थी कि अन्य राज्यों से नियुक्त किए गए 294 विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रभारियों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित 20-25 पृष्ठों की एक फ़ोल्डर दी गई थी। इसमें स्थानीय मुद्दे, पिछले कुछ चुनावों का मतदान पैटर्न, क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता, विभिन्न दलों के प्रमुख पदाधिकारियों के विवरण और संपर्क, साथ ही उनकी कमजोरियां और ताकतें जैसी जानकारियां भी शामिल थीं।

2016 से डेटा तैयार कर रही थी टीम

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन के नेताओं ने जिस डेटा का इस्तेमाल किया था। वह 20216 से बीजेपी के लिए काम करने वाली राजनीतिक रणनीति बनाने वाली एक कंपनी ने जुटाया था। कंपनी के डेटा को देख स्थानीय स्तर के नेता भी काफी चौंक गए थे। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने कहा, "हम विधानसभा क्षेत्रों में सभी आवश्यक आंकड़ों से लैस थे। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता अक्सर जमीनी स्तर की जानकारी और अन्य दलों के नेताओं के बारे में हमारे ज्ञान और समझ से आश्चर्यचकित रह जाते थे। सूची में यह भी शामिल था कि हमारे क्षेत्र में टीएमसी के कौन से नेता अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए काम कर सकते हैं और उनसे संपर्क किया जा सकता है।"

टीएमसी ने भी दिया मौका

संघ के नेताओं ने कहा कि टीएमसी की वजह से आरएसएस और बीजेपी का विकास हो सकता है। चुनाव के दौरान राज्य भर में तैनात रहे कोलकाता के संघ एक वरिष्ठ प्रचारक ने कहा, "अगर टीएमसी सरकार नहीं होती, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत संभव नहीं होती। राज्य में हमारा काम टीएमसी के उदय और मजबूती के साथ बढ़ा और ममता बनर्जी के नेतृत्व में उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण नीतियों के कारण राज्य में सांप्रदायिक विभाजन और भी गहरा गया। 2011 से पहले हमारे पास बहुत कम बंगाली प्रचारक थे। ये वैसी ही स्थिति थी, जैसी पंजाब में बीजेपी की है, जहां उसके पास बेहद कम प्रचारक थे। अब हमारे पास बंगाली प्रचारकों की एक लंबी सूची है, जिनमें न केवल पश्चिम बंगाल मूल के लोग हैं, बल्कि बांग्ला भाषी लोग भी शामिल हैं।"एक अन्य आरएसएस पदाधिकारी ने कहा, "वामपंथी शासन के दौरान सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करना मुश्किल था। टीएमसी के शासनकाल में यह बहुत आसान हो गया।" टीएमसी के शासनकाल में संघ के विस्तार की ओर इशारा करते हुए अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि राज्य भर में आरएसएस की 1,500 से अधिक दैनिक शाखाएं संचालित होती थीं। अगर यदि साप्ताहिक और मासिक सभाओं का जिक्र करें तो ये संख्या और ज्यादा प्रभावशाली भी नजर आएगी।

किसी राज्य में RSS को नहीं हुई बंगाल जैसी दिक्कतें

आरएसएस नेता ने कहा, "समय बीतने के साथ हमने महसूस किया कि बंगाली हिंदुओं के बीच टीएमसी और उसके नेतृत्व के प्रति एक प्रकार की नफरत बढ़ रही थी। हमने पाया कि जिन महिलाओं से हम संपर्क कर रहे थे, उनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई थीं। आरएसएस के नेताओं ने कहा कि शाखाएं आयोजित करना संघ के लिए काफी मुश्किल हो गया था। इसको लेकर एक पदाधिकारी ने कहा कि शायद और कोई राज्य ऐसा नहीं था, जहां हमारे लिए संघ की शाखा का आयोजन करना काफी मुश्किल था। टीएमसी के प्रभुत्व वाले स्थानीय निकायों ने अक्सर आयोजन स्थलों को बंद कर दिया, शौचालयों को रोक दिया और सभाओं में बाधा डाली। यह स्थिति केरल में आरएसएस के प्रति वामपंथियों के प्रतिरोध से कहीं अधिक व्यापक थी। संघ के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार ये हमले विशेष रूप से दक्षिण बंगाल में तीव्र थे। राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस से संबद्ध एक संगठन के लिए काम करने वाले पश्चिम बंगाल के एक प्रचारक ने बताया, "हमने महसूस किया कि बंगाली हिंदू ममता बनर्जी के नेतृत्व और नीतियों से तेजी से असहज महसूस करने लगे थे। समाजवादी पार्टी की सरकारों विशेष रूप से 2012-17 वाली सरकार ने हमें उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दिया।

शिक्षा शाखा से जुड़े स्कूलों पर पड़ते थे छापे

आरएसएस की शिक्षा शाखा, विद्या भारती, राज्य में लगभग 300 शारदा शिशु तीर्थ स्कूल चलाती है, जिनमें 1.5 लाख छात्र पढ़ते हैं और लगभग 3,000 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा शाखा से जुड़े एक प्रचारक ने बताया कि इन संस्थानों को बार-बार कानूनी मामलों, छापों और मान्यता रद्द होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। संघ के एक प्रचारक ने बताया, "हमारे स्कूलों पर बार-बार छापे मारे गए और आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई।"

विपक्ष के सामने अस्तित्व की चुनौती, बंगाल जैसा रहा हाल तो बंद हो जाएंगी राजनीति की खिड़कियां

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.जिस बंगाल को कभी बीजेपी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक जमीन माना जाता था, वहां जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर है. लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को रोका कैसे जाए? क्योंकि बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की एकता, नेतृत्व और रणनीति तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. बंगाल में बीजेपी की जीत ने यह साफ कर दिया है कि अब पार्टी सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रही. बीजेपी ने बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की राजनीति को हिंदुत्व और वेलफेयर के बड़े नैरेटिव से काउंटर किया. मुफ्त योजनाएं, मजबूत संगठन और हिंदुत्व की भावनात्मक राजनीति इस तिकड़ी ने बीजेपी को बंगाल में ऐतिहासिक बढ़त दिलाई.

भाषा और क्षेत्रीय पहचान के ऊपर एक राजनीति

सबसे बड़ा संदेश यह गया कि भाषा और क्षेत्रीय पहचान से ऊपर भी एक राजनीतिक पहचान तैयार की जा सकती है. यानी जिस तरह बंगाल में हिंदुत्व ने अपनी जगह बनाई, उसी तरह दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर भी बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है. उस आत्मविश्वास के जवाब में अब विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा होता दिख रहा है. राहुल गांधी ने उनसे बात कर 'वोट चोरी' का आरोप उठाया, वहीं अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचकर ममता से मिले और कहा कि दीदी, आप हारी नहीं हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत वोट प्रतिशत में साफ दिखाई देती है. बीजेपी को 45.84% वोट मिले, जबकि टीएमसी को 40.80%. CPM को 4.45%, CPI-RSP समेत अन्य वाम दलों को करीब 1% और कांग्रेस को 2.97% वोट मिले. यानी पूरे विपक्ष का वोट शेयर जोड़ दें तो आंकड़ा 48.66% बैठता है, जो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा है. यानी बीजेपी जितने अंतर से आगे निकली, लगभग उतना ही वोट टीएमसी से अलग बाकी विपक्षी दलों के खाते में चला गया. यही इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश भी है. विपक्ष की हार सिर्फ़ जनाधार की नहीं, बल्कि बिखराव की भी कहानी है.

'वोट बंटवारे' बनाम 'वोट चोरी' की राजनीति

INDIA गठबंधन खुद 'एकता में अनेकता' का प्रतीक है. कई राज्यों में इसके सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं. ऐसे में विपक्ष अब 'वोट बंटवारे' बनाम 'वोट चोरी' की राजनीतिक लाइन पर खड़ा दिख रहा है और यही नैरेटिव आगे भी चलाया जाएगा कि 'जहां-जहां SIR हुआ, वहां-वहां विपक्ष हारा. खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी पहले से मजबूत संगठनात्मक आधार रखती है. लेकिन पश्चिम बंगाल का गणित विपक्षी दलों के लिए एक राजनीतिक अलार्म भी है. आने वाले चुनावों में यूपी, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी दलों को आपसी फूट से ऊपर उठकर सोचना होगा. क्योंकि अगर विपक्षी वोट इसी तरह अलग-अलग खेमों में बंटता रहा, तो कई राज्यों में बीजेपी को सीधा फायदा मिलता रहेगा भले ही कुल विपक्षी वोट प्रतिशत उससे ज्यादा क्यों न हो. बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी उजागर कर दी. बीजेपी विरोधी वोट एकजुट नहीं हो पाए. कांग्रेस, वाम दल और क्षेत्रीय पार्टियां अलग-अलग लड़ती रहीं और बीजेपी इसका फायदा उठाने में सफल रही. राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एकता की बात करता है, लेकिन राज्यों में वही दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं. यही वजह है कि बीजेपी का वोट लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि विपक्षी वोट बिखर रहा है.

ये विपक्ष के लिए सिर्फ हार नहीं

अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गठबंधन बनाने की नहीं, बल्कि साझा नेतृत्व और साझा नैरेटिव तैयार करने की है. बंगाल की जीत ने बीजेपी को यह भरोसा दे दिया है कि अब देश का कोई भूगोल उसके लिए राजनीतिक रूप से अछूत नहीं बचा. लेकिन विपक्ष के लिए यह सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि चेतावनी है. अगर विपक्ष ने समय रहते साझा रणनीति, साझा नेतृत्व और बीजेपी के मुकाबले मजबूत वैचारिक नैरेटिव तैयार नहीं किया, तो आने वाले समय में बीजेपी के लिए नए दरवाजे खुलते जाएंगे और विपक्ष के लिए राजनीति की खिड़कियां भी बंद होती जाएंगी.

कोलकाता के मंच पर जब ठहर गया वक्त: PM मोदी ने आखिर क्यों छुए इस 98 वर्षीय बुजुर्ग के पैर?

कोलकाता के मंच पर जब पीएम मोदी ने अचानक एक बुजुर्ग के पैर छुए, तो पूरा देश दंग रह गया। आखिर कौन हैं 98 वर्षीय माखनलाल सरकार, जिनके आगे सत्ता का शिखर भी नतमस्तक हो गया? 1952 के कश्मीर आंदोलन से लेकर सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी तक, उनके संघर्षों का रहस्यमयी सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पश्चिम बंगाल में सुबेंदु अधिकारी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का मंच आज एक ऐतिहासिक सियासी बदलाव से कहीं अधिक, मानवीय संवेदनाओं और 'कार्यकर्ता भक्ति' का गवाह बना। जब पूरा देश नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी का इंतजार कर रहा था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया जिसने न केवल वहां मौजूद एक लाख लोगों की भीड़ को भावुक कर दिया, बल्कि भारतीय राजनीति में शीर्ष नेतृत्व और जमीनी कार्यकर्ता के रिश्ते की एक नई इबारत लिख दी।

एक अनछुआ पल: जब सत्ता का शिखर 'त्याग' के आगे नतमस्तक हुआ

ब्रिगेड परेड ग्राउंड के विशाल मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उनकी नज़र एक झुकी हुई कमर लेकिन चमकती आँखों वाले 98 वर्षीय बुजुर्ग पर पड़ी। वे कोई और नहीं, सिलीगुड़ी के माखनलाल सरकार थे। जैसे ही माखनलाल जी ने पीएम का स्वागत करना चाहा, प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल किनारे कर उनके पैर छुए और उन्हें गले लगा लिया। यह केवल एक अभिवादन नहीं था, बल्कि भाजपा के उस 'अंतिम छोर के कार्यकर्ता' का सम्मान था, जिसने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया।

कौन हैं माखनलाल सरकार? 1952 के कश्मीर आंदोलन का वो 'वीर सिपाही'

आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने इस बुजुर्ग को इतनी अहमियत दी? इसका जवाब माखनलाल सरकार के संघर्षपूर्ण इतिहास में छिपा है। 98 वर्ष की आयु में भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए समर्पित माखनलाल जी उस दौर के नेता हैं जब बंगाल में 'दीपक' जलाना भी चुनौती थी। साल 1952 में जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर आंदोलन का बिगुल फूंका, तब माखनलाल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। कश्मीर में तिरंगा फहराने के दौरान उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प नहीं डिगा।

संगठन का वो 'मौन शिल्पी', जिसने एक साल में खड़े किए 10 हजार सदस्य

प्रधानमंत्री का उन्हें गले लगाकर पीठ थपथपाना उनके उस संगठनात्मक कौशल का सम्मान था, जिसने उत्तर बंगाल में भाजपा की नींव रखी। 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद, माखनलाल जी को जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे दुर्गम क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने महज एक साल के भीतर 10,000 नए सदस्य जोड़कर सबको हैरान कर दिया था। 1981 से लगातार सात वर्षों तक जिला अध्यक्ष रहना उनकी ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है।

शॉल, सम्मान और संदेश: गुरुदेव की छाया में कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज

मंच पर गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, पीएम मोदी ने माखनलाल जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस भावुक पल के जरिए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हर उस कार्यकर्ता को संदेश दिया जो संघर्ष के दौर में पार्टी के साथ खड़ा रहा। उन्होंने बताया कि सुबेंदु सरकार की यह जीत केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि माखनलाल सरकार जैसे लाखों तपस्वियों के दशकों के बलिदान का परिणाम है।

'सोनार बांग्ला' के उदय में राष्ट्रवाद की जीत

आज जब बंगाल में भाजपा की पहली सरकार शपथ ले रही है, तब माखनलाल सरकार की आँखों में आए आंसू इस बात के गवाह थे कि राष्ट्रवाद की जो लौ उन्होंने 1952 में जलाई थी, वह आज मशाल बन चुकी है। प्रधानमंत्री का यह आचरण सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ लोग इसे 'एक आदर्श नेता और एक समर्पित कार्यकर्ता का मिलन' कह रहे हैं।

असम में BJP ने लगाई जीत की हैट्रिक, सियासी वनवास खत्म नहीं कर पाई कांग्रेस

असम विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित हो गए हैं. 126 विधानसभा सीटों वाले सूबे की सत्ता एक बार फिर एनडीए के हिस्से आ गई है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाला NDA गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है. हिमंता बिस्वा सरमा ने असम की जालुकबारी विधानसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की है. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बिदीशा नेओग को 89 हजार 434 वोटों के भारी अंतर से हराया है. हिमंता बिस्वा सरमा ने इस सीट पर 1 लाख 27 हजार 151 वोट हासिल किए हैं. कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई 4 लाख 6 हजार 257 जोरहाट सीट से हार गए हैं. बीजेपी नेता हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने उन्हें 2 लाख 3 हजार 182 वोटों से मात दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम समेत तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है. जब सालों की साधना, सिद्धि में बदलती है, तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं.'

एक नया इतिहास रचा है- PM मोदी-पीएम मोदी ने कहा, 'मैं आज बंगाल के लोगों, असम के लोगों, पुडुचेरी के लोगों और तमिलनाडु और केरल के लोगों को आदरपूर्वक नमन करता हूं. मैं उन सभी को सलाम करता हूं. आज मैं BJP के अनगिनत कार्यकर्ताओं को भी दिल से बधाई देता हूं. BJP के हर छोटे-बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर चमत्कार किया है, कमल खिलाया है. आपने एक नया इतिहास रचा है.'

अमित शाह ने असम की जनता का किया धन्यवाद-गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बीजेपी की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, 'ऐतिहासिक हैट-ट्रिक जनादेश के लिए असम का धन्यवाद. ये पीएम मोदी की NDA सरकार की 10 साल की लगातार कोशिशों का एक जबरदस्त समर्थन है, जो सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील असम बनाने के लिए की गई हैं. आपका जबरदस्त प्यार और समर्थन आपकी बेहतर सेवा करने और आपकी उम्मीदों को पूरा करने के हमारे वादे को और मजबूत करता है.' राहुल गांधी ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'असम और बंगाल साफ तौर पर ऐसे मामले हैं जहां BJP ने EC के सपोर्ट से चुनाव चुराए हैं. हम ममता जी से सहमत हैं. बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गईं. हमने ये प्लेबुक पहले भी देखी है: मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 वगैरह में. चुनाव चोरी, संस्था चोरी - अब और चारा ही क्या है!' असम में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. इस बार चुनाव में भारी मतदान दर्ज किया गया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने पक्ष में माहौल बनता हुआ बता रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ, NRC, CAA, बाढ़, बेरोजगारी, चाय बागान मजदूरों की स्थिति और विकास जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे.

'कांग्रेस में हमारे कई धुरंधर हिमंता बिस्वा सरमा का दावा

असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी-एनडीए की प्रचंड जीत के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने बातचीत में बड़ा दावा किया है. उन्होंने हाल में आई आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा. हिमंता ने कहा कि कांग्रेस में हमारे धुरंधर हैं. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 30 उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके बीजेपी और उनसे अच्छे संबंध हैं. इनमें से 6 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. हिमंता बिस्वा सरमा से जब पूछा गया कि आपने दावा किया था कि कांग्रेस के 30 टिकट मैं दूंगा, तो आपके कितने उम्मीदवारों को विपक्षी दल ने टिकट दिया था इस बार? इस प्रश्न के जवाब में हिमंता ने कहा, 'हमारे साथ जिनके अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे 30 नेताओं को कांग्रेस ने टिकट दिया था, उनमें से 6 जीते.

कांग्रेस के बड़े नेता ही हमारी मदद करते हैं. खुलके मदद करते हैं. हमें हमारे एनिमी कैम्प में भी ऑपरेट करना है.' उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए कहा, 'जैसे आपने धुरंधर देखा न पाकिस्तान में जैसे काम करते थे. तो हमारे भी धुरंधर कांग्रेस में हैं.' क्या हिमंता के के जासूस हैं कांग्रेस में? इस पर उन्होंने कहा, 'जासूस नहीं हैं. उनका भी अपना पॉलिटिकल करियर है. वे बीजेपी में आने पर नहीं जीतेंगे.

इसलिए उनको कांग्रेस में ही रहकर देश की सेवा करना है और बीजेपी की मदद करते रहना है.' असम में कांग्रेस के जो 19 उम्मीदवार जीते हैं, उनमें 18 मुस्लिम हैं.

थलपति विजय ने 14 साल की बच्ची की अपील पर अपनी VIP कुर्सी के पीछे से सफेद तौलिया हटाया

चेन्नेईः अभिनेता से नेता बने थलपति विजय ने जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसा काम किया है जिसे लेकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल विजय ने अपनी वीआईपी कुर्सी के पीछे से सफेद तौलिए को हटा दिया है। दरअसल सरकारी दफ्तरों की कुर्सियों पर अक्सर वीआईपी कुर्सियों के पीछे एक सफेद तौलिया लटका रहता है। विजय की कुर्सी पर भी पहले यह सफेद तौलिया मौजूद था। लेकिन अब उन्होंने इसे चुपचाप हटा दिया है। उन्होंने यह एक 14 साल की बच्ची की अपील पर किया है।

14 साल की एक्टिविस्ट ने की थी खास अपील

बता दें कि मात्र 14 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने विजय से एक खास अपील की थी। कंगुजम ने एक्स पर विजय को टैग करते हुए एक पोस्ट लिखी थी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि नमस्ते @TVKVijayHQ सर, क्या हम भारत में VIP कुर्सियों पर तौलिया रखने की इस 'तौलिया संस्कृति' को खत्म कर सकते हैं? लोग पहले से ही जानते हैं कि भारत में मुख्यमंत्री (CM) VIP होते हैं। इस तौलिया संस्कृति का पालन मंत्री, नौकरशाह और यहां तक कि छोटे अधिकारी भी कर रहे हैं। सर, आप एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। आप इस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं।

सीएम विजय ने लिया एक्शन

कंगुजम की इस अपील के 24 घंटे के भीतर थलपति विजय ने एक्शन लिया और बिना किसी आधिकारिक घोषणा या प्रचार के चुपचाप अपनी कुर्सी से सफेद तौलिया हटा दिया। कंगुजम ने ऐसा करने पर विजय का धन्यवाद किया। कंगुजम ने फिर एक ट्वीट किया और लिखा कि धन्यवाद विजय सर। आपके इस कदम से यह साबित होता है कि आप आम लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं। बदलाव आ रहा है, चाहे हमें यह पसंद हो या न हो।

यूजर भी कर रहे तारीफ

मुख्यमंत्री विजय के इस कदम को अब तमिलनाडु की राजनीति में नई कार्यशैली के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे वीआईपी संस्कृति से दूरी बनाने की सकारात्मक शुरुआत बताया है। वहीं कुछ यूजर्स का मानना है कि ऐसे बदलाव प्रशासनिक व्यवहार में भी सादगी और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस बदलाव पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह मुद्दा अब राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है।

सीएम बनते ही TVK चीफ ने कही ये बात

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK चीफ सी जोसेफ विजय ने कहा, ₹तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है. एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद ही कोई सही मायने में हालात और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को समझ सकता है लेकिन मैं ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहता हूं, मैं इस राज्य की हर महिला को भरोसा दिलाता हूं कि उनकी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होगी और महिलाओं को टारगेट करने वाले क्राइम के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा. ड्रग्स से परेशान लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, हम उन्हें बचाने और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करेंगे और एक हेल्दी समाज बनाएंगे.

1.3 करोड़ महिलाओं के खाते में डाले एक-एक हजार रुपये

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही थलपति विजय की सरकार ने शुक्रवार को 'कलाईनार मगलीर उरिमाई थिट्टम' (KMUT) के तहत करीब 1.3 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि जमा कर दी। इसके साथ ही योजना को लेकर चल रही अनिश्चितता भी खत्म हो गई है। दरअसल, TVK सरकार इस योजना को नए स्वरूप में लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, योजना को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कदम TVK के चुनावी वादे के अनुरूप माना जा रहा है, जिसमें 60 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2500 देने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में महिलाओं को 1000 की सहायता राशि दी जा रही है।

पुडुचेरी में फिर से रंगासामी की सरकार

पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एन. रंगासामी ने पांचवी बार ली पुडुचेरी के सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ ए नमशिवायम और मल्लादी कृष्ण राव भी मंत्री बने। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने एआईएनआरसी के संस्थापक एन. रंगासामी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और वरिष्ठ नेता बीएल संतोष भी मौजूद रहे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज कर सत्ता बरकरार रखी थी।

रंगास्वामी ने बनाया दिया रिकॉर्ड

एन. रंगास्वामी चार बार (2001-2006, 2006-2008, 2011-2016 और 2021 से अब तक) पुडुचेरी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने कहा कि मुझे इस बात से बेहद खुशी हो रही है कि मैंने पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला है। हम लोगों की भलाई और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। मेरी सरकार हर उस कदम को लागू करेगी, चाहे वह किसी खास काम में तेज़ी लाना हो या नई योजनाएं शुरू करना, जिससे राज्य के विकास में मदद मिले। बाकी मंत्री भी जल्द ही अपने पद की शपथ लेंगे।

पुडुचेरी में एनडीए को मिली है जीत

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 सीटें हासिल की हैं। 30 सीटों वाले पुडुचेरी में लगातार दूसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस 12 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है।

दूसरी ओर, कांग्रेस-डीएमके गठबंधन को छह सीटें मिलीं। इसमें कांग्रेस ने एक और द्रविड़ मुनेत्र कज़गम ने 5 सीटें जीतीं। जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले टीवीके-नेयम मक्कल कझगम गठबंधन को तीन सीटें मिलीं। इसमें टीवीके ने 2 और नेयम मक्कल कझगम ने 1 सीट जीती। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की।

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआईएनआरसी) के संस्थापक एन. रंगासामी को बधाई दी और कहा कि उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में अपनी छाप छोड़ी है और केंद्र शासित प्रदेश के विकास पथ को मजबूत किया है। मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया। इसमें लिखा कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर थिरु एन. रंगासामी जी को हार्दिक बधाई। उन्होंने एक अनुभवी और कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है और पुडुचेरी के विकास को मजबूती दी है। जनता के कल्याण के लिए उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। आगामी कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।

'मुझे अपार खुशी हो रही है':

शपथ ग्रहण समारोह के बाद बोलते हुए रंगासामी ने कहा, "पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवीं बार पदभार ग्रहण करना मेरे लिए अपार प्रसन्नता का विषय है। हम जनता के हित और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। मेरी सरकार राज्य के विकास में योगदान देने वाले हर उपाय को लागू करेगी, चाहे वह विशिष्ट कार्यों में तेजी लाना हो या नई योजनाओं की शुरुआत करना हो।

19 हजार के लिए कंकाल निकाला, अब मिले 15 लाख

क्योंझर, ओडिशा ,इसमें दिख रहे शख्स जीतू मुंडा हैं। उम्र 52 साल। बदन पर सिर्फ एक कपड़ा। कंधे पर बड़ी बहन कलरा का कंकाल। कलरा के बैंक अकाउंट में 19,400 रुपए जमा थे। उनकी मौत के बाद जीतू 27 अप्रैल को पैसे निकालने बैंक पहुंचे। आरोप है कि बैंक मैनेजर ने कहा कि बहन को लाओ, तभी पैसे मिलेंगे। जीतू ने कब्र से बहन का कंकाल निकाला और तीन किमी दूर बैंक लेकर आ गए। मामला ओडिशा के क्योंझर जिले के दियानाली गांव का है। कभी भी टूटकर गिर जाने की हालत में पहुंच चुका ये मकान जीतू का घर है। कच्चा फर्श, सीलन भरी दीवारें, दरवाजे की चौखट तक उखड़ चुकी है। पहले जीतू और उनकी बहन कलरा इसी घर में रहते थे। दो गाय भी इसी में बंधती थीं। एक साल पहले कलरा को सरकारी घर मिल गया। जीतू के पास कोई काम नहीं है। कलरा को सरकार से मिलने वाले 1 हजार रुपए और 35 किलो चावल में गुजारा होता था।

पति की मौत के बाद से कलरा मायके में रह रही थीं। उन्होंने बछड़ा बेचकर 19,400 रुपए पटना ब्लॉक के मल्लीपासी ग्रामीण बैंक में जमा किए थे। जीतू और कलरा बीच-बीच में 100, 200, 500 रुपए निकालने बैंक जाते थे। एक दिन कलरा बीमार पड़ीं और 26 जनवरी को उनकी मौत हो गई। जीतू के गुजारे का सहारा खत्म हो गया। आखिरी आस बैंक में जमा पैसे थे। जीतू वही निकालने बैंक गए थे।

19 हजार के लिए बहन की कब्र खोदी, अब 15 लाख रुपए की मदद मिली-जीतू के घर में बहन के अलावा एक भाई और उनका परिवार है। जीतू की शादी नहीं हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें बैंक में जमा पैसों के अलावा अलग-अलग संगठनों और पार्टियों से करीब 15 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है। बहन के घर में बिजली कनेक्शन मिल गया है। जीतू अब उनके घर में ही रह रहे हैं। जीतू का गांव क्योंझर से करीब 40 किमी दूर जंगलों में बसा है। हम उनके घर पहुंचे तो मीडिया और नेताओं की भीड़ लगी थी। जीतू, उनके भाई शंकर और बहन कलरा के घर पास-पास ही हैं, लेकिन जीतू और कलरा साथ में जीतू के घर में रहते थे। फिर कलरा नए घर में रहने लगीं। इसी घर के पास उनकी कब्र बनी है।

मुंडा समुदाय में शव को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। जीतू मुंडा और परिवार ने बहन की मौत होने पर उन्हें घर के पास ही दफना दिया।

हमने जीतू से पूछा घर के पास बहन की कब्र क्यों बनाई है? जीतू बोले- मेरी बहन ही मेरा घर है। मुझे डर नहीं लगता। वह मेरे पास ही है। बहन के जाने के बाद अकेला हो गया हूं। माता-पिता के निधन के बाद वही मेरे लिए सब कुछ थीं। मेरे पास न राशन कार्ड है, न

कोई कागज। सब बहन का ही था।

जीतू इससे आगे नहीं बोल पाते। उनके छोटे भाई शंकर बताते हैं कि जिस दिन जीतू ने बहन की कब्र खोदी थी, मैं घर पर नहीं था। जीतू और कलरा के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। दोनों कई बातों में मुझे भी शामिल नहीं करते थे। मुझे बताए बिना ही बैंक जाते थे। हम चार भाई थे। दो भाइयों का निधन हो चुका है। पति की मौत के बाद कलरा भी हमारे पास आ गई। वह जीतू के साथ रहने लगी। वो कहती थी कि अब भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी।

जीतू ने कब्र खोदी, बहन का कंकाल निकाला, तब आसपास के लोगों ने रोका क्यों नहीं? जवाब गांव के मंसूर ने दिया, 'जीतू उस दिन सुबह करीब 10 बजे बैंक गया था। 11:30 बजे लौटा। 12 बजे के करीब कब्र खोदना शुरू किया। तेज गर्मी की वजह से आसपास सन्नाटा था, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाया।'

कलरा की मौत कैसे हुई थी? पड़ोसी करुणाकर महंत बताते हैं, 'तेज बुखार हुआ था। जीतू बैंक गया और 500 रुपए निकालकर लाया। कलरा को अस्पताल ले गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके तीन महीने बाद जीतू पैसे निकालने बैंक गया था। स्टाफ ने उससे कागज मांगे। जीतू पढ़ा-लिखा नहीं है, उसे कागजों के बारे में पता नहीं था। वो एक ही बात कहता रहा कि मेरी बहन के नाम पर पैसा है, मुझे दे दो। स्टाफ ने कहा कि जाओ, बहन को लेकर आओ, तब पैसा मिलेगा।'

'हो सकता है बैंकवालों ने यह बात झुंझलाहट में कही हो, लेकिन जीतू उसे समझ नहीं पाया। वो गांव लौटा और कब्र खोदकर बहन का कंकाल निकाला। तीन किलोमीटर दूर बैंक ले गया। मैनेजर से कहा कि मैं बहन को ले आया हूं, अब मेरा पैसा दे दो। स्टाफ ने पुलिस बुला ली। पुलिसवालों ने जीतू को डांटा और कहा कि शव को फिर से दफनाओ। जीतू कंकाल कंधे पर रखकर वापस लाया और उसे फिर से दफना दिया।'

पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी-बैंक मैनेजरः मैनेजर के मुताबिक, जीतू पैसे निकालने आया था, तभी उसे पहली बार देखा था। उससे डॉक्युमेंट मांगे थे, डेडबॉडी लाने के लिए नहीं कहा। हालांकि, जीतू का दावा है कि मैनेजर ने ही कहा था कि बहन को लेकर आओ, तब पैसा मिलेगा। जीतू के मुताबिक, मैंने मैनेजर को बताया भी था कि बहन मर चुकी है, तब भी उन्होंने कहा कि बहन को लेकर आओ, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा।

जांच में सामने आया है कि जीतू बहन के साथ कई बार बैंक आए थे। आखिरी बार दोनों 26 दिसंबर को 500 रुपए निकालने बैंक गए थे। हम मल्लिपासी ग्रामीण बैंक गए, जहां जीतू की बहन का अकाउंट है। बैंक मैनेजर मौजूद नहीं थे। सिर्फ दो कर्मचारी थे, जिनमें से एक डेपुटेशन पर हैं। उन्होंने बताया कि मैनेजर छुट्टी पर चले गए हैं।ये मल्लिपासी ग्रामीण बैंक की ब्रांच है। ये ब्रांच पटना ब्लॉक में है। जीतू मुंडा की बहन कलरा का अकाउंट इसी बैंक में था।ये मल्लिपासी ग्रामीण बैंक की ब्रांच है। ये ब्रांच पटना ब्लॉक में है। जीतू मुंडा की बहन कलरा का अकाउंट इसी बैंक में था।

आम जनता से शालीनता से पेश आएं अधिकारी

न्यूज रुटीन @ रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रशासनिक व्यवस्था को जनकेंद्रित और संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से शासकीय अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं कि वे आमजन के साथ शालीनता, धैर्य और सम्मान के साथ व्यवहार करें। उन्होंने दो टूक कहा कि मुख्यालय और फील्ड स्तर पर शासकीय अधिकारी ही शासन का चेहरा होते हैं, इसलिए उनका आचरण शासन की छवि को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुनना प्रशासनिक अधिकारियों का पहला कर्तव्य है। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि वे जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और समाधान पर केंद्रित रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवाद तभी सार्थक है, जब उसमें संवेदना और समस्याओं का समाधान करने की नीयत हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभागों में जनसमस्याओं के निराकरण को प्रभावी, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए। जब कोई आम नागरिक किसी शासकीय कार्यालय पहुंचे, तो उसे यह महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सकारात्मक अनुभव ही जनता के मन में विश्वास पैदा करता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों के अनुभव से मापी जाती है। इसलिए अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें, लोगों से सीधे संवाद करें और उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कार्य करें। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता और तत्परता ही प्रशासन की असली ताकत है। उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही को अपने कार्य का मूल आधार बनाने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे बनाए रखने के लिए ईमानदारी के साथ-साथ व्यवहार में शालीनता और विनम्रता भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुशासन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि व्यवहार से स्थापित होता है। यदि अधिकारी जनता के साथ सरल, सहज, सहयोगात्मक और जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण का तरीका हर समय अपनाते हैं, तो प्रशासन स्वयमेव अधिक प्रभावी हो जाता है और शिकायतों की संख्या स्वतः कम होने लगती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का सपना तभी साकार होगा, जब प्रशासन हर नागरिक के लिए सुलभ, संवेदनशील और सम्मानजनक बने। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे इस भावना को अपने कार्य का मूल मंत्र बनाकर आगे बढ़ें और हर व्यक्ति को यह अहसास दिलाएं कि सरकार उसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया कि सुशासन तिहार के दौरान वे स्वयं विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के कार्य के साथ-साथ उनके व्यवहार पक्ष का भी अवलोकन करेंगे। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के दौरान अधिकारियों की संवेदनशीलता, शालीनता और जवाबदेही को प्राथमिकता के साथ परखा जाएगा।

लोगों की सुनें, लोगों को सुनाए नहीं - मुख्यमंत्री का अधिकारियों को दो टूक निर्देश

मिट्टी के बर्तन में बोरे-बासी पर सियासत,क्या वे कांग्रेस का पिंडदान करने गए थे: गजेन्द्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बोरे बासी दिवस को लेकर सियासत तेज हो गई है। 1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिट्टी के बर्तन में बोरे बासी खाकर बोरे बासी दिवस मनाया था, जिसको लेकर अब स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने उनपर हमला बोला है। उन्होंने इसे प्रोपेगेंडा बताया है। दरअसल, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रवाना होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। दुर्ग में भूपेश बघेल की ओर से मिट्टी के बर्तन में बोरे बासी खाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिट्टी के बर्तन में बोरे बासी खाकर भूपेश बघेल ने प्रोपेगेंडा किया। पिंडदान और पितृ भोज में मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है। भूपेश बघेल क्या कांग्रेस पार्टी का पिंडदान करने गए थे। आगे कहा कि कांग्रेस त्योहार मनाकर क्या साबित करना चाहती है। क्या छत्तीसगढ़ के लोग बासी ही खाएं ? स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बंगाल समेत 5 राज्यों के परिणाम को लेकर कहा कि रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा और बंगाल में सुनामी के रूप में भाजपा की सरकार आएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पांच राज्यों में से तीन राज्यों में स्पष्ट भाजपा की सरकार बनेगी। इसी के साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मेधावी छात्रों को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि मेरिट लिस्ट में आने वाले 10वीं और 12वीं के बच्चों को सरकार एक साथ 1 लाख 50 हजार रुपए देगी, जिससे बच्चों को पढ़ाई में सुविधा होगी। वहीं मंत्री गजेंद्र यादव ने बच्चों को हेलीकॉप्टर यात्रा के सवाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को 1 लाख 50 हजार देंगे। हम किसी की नकल नहीं करते हैं। पिछले सरकार में बच्चे एक बार ही हेलीकॉप्टर यात्रा पर घूमते थे, लेकिन 1 लाख 50 हजार रुपए में बच्चे अपने पूरे परिवार के साथ पैकेज घूमकर आ सकते हैं।

सुशासन तिहार में सीएम ने जीत लिया लोगों का दिल

न्यूज रुटीन @ जशपुर

सुशासन तिहार के दौरान जशपुर जिले के ग्राम भैंसामुड़ा में एक ऐसा आत्मीय और भावुक क्षण सामने आया, जिसने वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के मन को गहराई से छू लिया और पूरे वातावरण को संवेदनाओं से भर दिया। यह दृश्य उस मानवीय स्पर्श का जीवंत उदाहरण बन गया, जहां शासन और संवेदना एक साथ दिखाई देते हैं।

सुशासन तिहार के दौरान जैसे ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की नजर 4 वर्षीय नन्हीं बच्ची मानविका चौहान पर पड़ी, वे सहज भाव से उसके पास पहुंच गए। उनके इस स्वाभाविक और अनायास कदम ने पूरे माहौल को एक अलग ही अपनत्व के वातावरण में बदल दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्नेहपूर्वक बच्ची को अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए उससे आत्मीय संवाद करने लगे। उनके चेहरे पर झलकता स्नेह और व्यवहार की सरलता इस बात को दर्शा रही थी कि सच्चा नेतृत्व वही होता है, जो लोगों के बीच जाकर उनके अपनेपन को महसूस करता है। मुख्यमंत्री श्री साय के पूछने पर मासूमियत भरी आवाज़ में जब मानविका ने तुतलाते हुए कहा - ₹मुझे डॉक्टर बनना है₹, तो उस छोटे-से वाक्य में एक बड़े सपने की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यह सुनकर मुख्यमंत्री श्री साय के चेहरे पर सहज और स्नेहिल मुस्कान उभर आई। उन्होंने पूरे अपनत्व के साथ बच्ची को आशीर्वाद दिया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह संवाद भले ही कुछ क्षणों का रहा, लेकिन उसमें जो भावनात्मक गहराई थी, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह महसूस कराया कि छोटे बच्चों के सपनों को भी सही प्रोत्साहन देने का कार्य भी मुख्यमंत्री का रहे हैं। इसी आत्मीयता में मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने पास रखा चश्मा निकालकर बड़े प्यार से बच्ची को पहनाया और उसे पुचकारते हुए उसका हौसला बढ़ाया।

मानविका की माता श्रीमती दीपांजलि चौहान ने बताया कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित थी और उनसे मिलकर अत्यंत खुश हुई। उन्होंने इस स्नेहपूर्ण व्यवहार के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए एक यादगार अनुभव बन गया है। यह पूरा प्रसंग संवेदनशील और जनसरोकार से जुड़े नेतृत्व का सजीव उदाहरण बन गया, जहां शासन केवल योजनाओं और नीतियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्नेह, संवाद और विश्वास के माध्यम से सीधे लोगों के दिलों तक अपनी जगह बनाता है। ग्राम भैंसामुड़ा में शासकीय प्राथमिक शाला चंदागढ़ के स्कूल मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री जब विद्यालय परिसर पहुंचे, तब उन्होंने स्कूल के मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा। बच्चों का उत्साह देखकर वे स्वयं रुक गए और उनके साथ मैदान में उतरकर क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत करते हुए पूछा कि वे नियमित रूप से खेलते हैं या नहीं और खेलकूद के प्रति उनकी रुचि के बारे में जानकारी ली।

आम की छांव में बदले सपनों के मायने: मुख्यमंत्री ने कहा अब करोड़पति दीदी बनने की सोचिए

कबीरधाम जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में सुशासन तिहार के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सरकारी योजनाओं के प्रभाव को आंकड़ों से आगे बढ़ाकर मानवीय संवेदनाओं से जोड़ दिया।

न्यूज रुटीन @ कवर्धा

4 मई को ग्रामपंचायत लोखान के कमराखोल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अचानक पहुंचने से ग्रामीणों, खासकर महिलाओं के लिए यह पल बेहद खास बन गया। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच आम के पुराने पेड़ की छांव में चौपाल सजी, जहां मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनसे सीधी बातचीत की। महिलाओं ने अपने जीवन के संघर्षों और बदलाव की कहानियां साझा कीं—आर्थिक तंगी और सीमित अवसरों से लेकर स्वयं सहायता समूहों के जरिए आत्मनिर्भर बनने तक का सफर।

बिहान योजना से जुड़कर कई महिलाओं के "लखपति दीदी" बनने की जानकारी मिलने पर संतोष जताते हुए उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और बड़े लक्ष्य तय करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर अब और आगे बढ़ते हुए बड़ा सपना देखना जरूरी है। ग्राम कुकदूर की कचरा तेलगाम ने अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि बिहान योजना से मिले ऋण से उन्होंने शटरिंग प्लेट्स खरीदकर व्यवसाय शुरू किया। लगातार प्रयासों से उन्होंने अपना काम बढ़ाया और अब वे कई निर्माण कार्यों में सहयोग कर रही हैं। इस कार्य से उन्हें सालाना अच्छी आय हो रही है, जिससे वे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां संभालने के साथ बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर पा रही हैं।

उन्होंने बताया कि पहले वे केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, लेकिन अब आत्मनिर्भर बनकर परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है। इस दौरे ने यह स्पष्ट किया कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में भी योजनाएं लोगों के जीवन में ठोस बदलाव ला रही हैं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई धुरी बन रही हैं।

चौपाल बनी आत्मविश्वास का मंच

आम के पेड़ की छांव में सजी चौपाल में महिलाओं ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां साझा कीं। स्वयं सहायता समूहों और बिहान योजना से जुड़कर वे आर्थिक रूप से मजबूत बनी हैं और गांवों में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रही हैं।

सपनों को मिली नई उड़ान

महिलाओं को "लखपति दीदी" से आगे बढ़कर बड़े लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे वनांचल क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता और बड़े सपने देखने का नया उत्साह पैदा हुआ है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समाज के समग्र विकास से जोड़ते हुए यह भी कहा गया कि जब महिलाएं मजबूत होती हैं, तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है।

देश की प्रगति और राष्ट्रीय एकता में क्षत्रिय कुर्मी समाज का योगदान अविस्मरणीय : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर.छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि देश की प्रगति और राष्ट्रीय एकता में क्षत्रिय कुर्मी समाज का योगदान अविस्मरणीय रहा है। वे कबीरधाम जिले के डोंगरिया में आयोजित अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक संगठित, जागरूक और सशक्त समाज ही मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होता है। कुर्मी समाज ने अपने परिश्रम, सामाजिक चेतना और संगठन के बल पर देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को सिंचाई, सड़क और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जलेश्वर महादेव धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

गौरवशाली इतिहास और प्रेरणादायक व्यक्तित्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुर्मी समाज का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान व्यक्तित्वों ने राष्ट्र निर्माण, एकता और सुरक्षा में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज खेती-किसानी से लेकर शिक्षा, प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण और योजनाओं का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बना है। उन्होंने बताया कि रामलला दर्शन योजना के तहत अब तक

लगभग 42 हजार श्रद्धालु अयोध्या की यात्रा कर चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को देश के 19 प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जा रही है।

विकास और जनकल्याण के कार्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार "मोदी की गारंटी" को जमीनी स्तर पर लागू कर रही है। महतारी वंदन योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10,500 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और रेलवे अधोसंरचना के विस्तार पर भी तेजी से काम चल रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ को भी एक विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। प्रदेश की पांच प्रमुख शक्ति पीठों को विकसित कर धार्मिक एवं सांस्कृतिक कॉरिडोर के रूप में जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

अन्य वक्ताओं के विचार

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता और संगठन में निहित होती है।

राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कुर्मी समाज की एकजुटता और संस्कारों को उसकी सबसे बड़ी ताकत बताया।

तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने भी समाज की प्रगतिशील भूमिका पर प्रकाश डाला।

अखिल भारतीय क्षत्रिय कुर्मी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश कटियार ने कहा कि समाज की संगठनात्मक परंपरा 132 वर्षों से अधिक पुरानी है और इसकी एकता व सामाजिक मूल्यों ने देशभर में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।

राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ की राजनीति में पक्ष-विपक्ष की बयानबाजी से सभी वाकिफ है। लेकिन मौजूदा वक्त में सूबे की राजनीति में बयानबाजी का स्तर अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जीं हां राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव से कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने जनता के सामने कह दिया कि अगर एक महीने में सड़क नही बना, तो मेरे नाम पर कुत्ता पाल लेना। नेतीजी के इस बयान को सुनन के बाद ग्रामीण भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए कि सड़क मांगने आए थे या कोई नया 'पालतू पशु योजना' लॉन्च हो गई है ! जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला राजनांदगांव के कोपेडीह से बोदेला गांव तक की सड़क का है, जो वर्षों से राजनेताओं के भाषणों में तो बन चुकी है। लेकिन जमीन पर अब भी गड्ढों के बीच अपनी किस्मत तलाश रही है। ग्रामीणों के तीखे विरोध को देखकर विधायक दलेश्वर साहू ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यदि एक महीने के भीतर गांव की सड़क नहीं बनती है तो "मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना।" विधायक के इस बयान के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए।

वहीं अब यह बयान राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल भी इसे लेकर कांग्रेस विधायक पर निशाना साध रहे हैं। सोशल मीडिया पर बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि डोंगरगांव मुख्य मार्ग और क्षेत्र की सड़कों को लेकर विधायक दलेश्वर साहू की भूमिका पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। विधायक ने जिस सड़क परियोजना को अपना "ड्रीम प्रोजेक्ट" बताया था, वह करीब चार साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में सड़क निर्माण को लेकर जनता की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विधायकजी के इस बयान के बाद अब जनता समझ नहीं पा रही कि इसे आश्वासन माना जाए, चेतावनी माना जाए या फिर चुनावी वादों का नया "एनिमल एडिशन" ! ग्रामीण सड़क मांग रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें ऐसा डायलॉग मिल गया, जो सीधे सोशल मीडिया की हेडलाइन बन गया। गांव वालों ने शायद पहली बार देखा होगा कि विकास कार्यों की गारंटी अब टेंडर या बजट से नहीं, बल्कि "कुत्ता पालने" की शर्तों पर दी जा रही है। फिलहाल सड़क बने या न बने, लेकिन विधायक जी का बयान जरूर वायरल रोड पर फुल स्पीड से दौड़ रहा है।

प्रमोशन की खुशियां बदली मातम में, पदोन्नति के बाद ज्वाइन करने जा रहे अफसर

कोरबा। दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के वरिष्ठ अधिकारी आर के त्यागी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वे हाल ही में पदोन्नति मिलने के बाद नई जिम्मेदारी संभालने के लिए सिंगरौली जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे-130 पर बांगो थाना क्षेत्र के चोटिया के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। इस घटना के बाद एसईसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों में गहरा शोक व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक, आरके त्यागी को हाल ही में डायरेक्टर टेक्निकल पद पर पदोन्नत किया गया था। वे लंबे समय से एसईसीएल में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे थे और उनकी पहचान एक अनुभवी एवं कुशल अधिकारी के रूप में थी। गुरुवार देर रात करीब 12 बजे वे गेवरा क्षेत्र से इनोवा कार में सवार होकर सिंगरौली के लिए रवाना हुए थे। बताया जा रहा है कि जब उनकी कार बांगो थाना क्षेत्र के चोटिया के पास पहुंची, तभी सामने चल रहे एक पार्सल वाहन से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इनोवा कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद आरके त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें उपचार के लिए अपोलो अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन शुक्रवार सुबह करीब तीन बजे डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही एसईसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों में शोक की लहर दौड़ गई। कई कर्मचारियों ने इसे संस्थान के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। घटना की सूचना मिलते ही बांगो पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही को माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आरके त्यागी एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र में महाप्रबंधक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। सहकर्मियों के अनुसार वे अनुशासित, सरल स्वभाव और कार्य के प्रति समर्पित अधिकारी थे। इस हादसे ने एक बार फिर नेशनल हाईवे-130 की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते कुछ समय से इस मार्ग पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। भारी वाहनों की तेज आवाजाही, ओवरस्पीड और लापरवाही के कारण यह हाईवे हादसों का केंद्र बनता जा रहा है।

“गब्बर फाइल्स -अब सच दबेगा नहीं... दर्ज होगा” : अकील

न्यूज रुटीन @ रायपुर / अम्बिकापुर । विशेष रिपोर्ट

व्यवस्था की खामियों, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और आम जनता की अनसुनी शिकायतों के बीच एक नई डिजिटल जन-पहल सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी ने अपने फेसबुक वाल के माध्यम से “गब्बर फाइल्स — सच का डिजिटल रिकॉर्ड” नामक एक वैधानिक डिजिटल मंच शुरू करने की घोषणा की है।

इस पहल का उद्देश्य आम जनता, पीड़ित व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, कर्मचारियों और ईमानदार अधिकारियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना बताया गया है, जहाँ वे जनहित से जुड़े दस्तावेज़, शिकायतें और डिजिटल साक्ष्य साझा कर सकें।

“सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी”

अपने विस्तृत पोस्ट में अकील अहमद अंसारी ने वर्तमान व्यवस्था की कई गंभीर समस्याओं का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि आज देश का आम आदमी रोज़ सिस्टम से लड़ रहा है। कहीं सड़कें कागज़ों में बन जाती हैं लेकिन ज़मीन पर टूटी रहती हैं, कहीं अस्पतालों में इलाज नहीं, तो कहीं स्कूलों में शिक्षा का स्तर कमजोर है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना रिश्वत कई लोगों का काम नहीं हो पा रहा, कई लोग झूठे मामलों, ज़मीन फर्जीवाड़े, सरकारी लापरवाही और निजी संस्थाओं की मुनाफाखोरी से परेशान हैं। पोस्ट में यह सवाल भी उठाया गया कि आखिर आम जनता अपनी शिकायत लेकर जाए तो कहाँ जाए?

“ईमानदार अधिकारी भी परेशान”

पोस्ट में केवल जनता की समस्याओं का ही उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि सिस्टम के भीतर कार्यरत ईमानदार कर्मचारियों और अधिकारियों की परेशानियों को भी सामने लाने की कोशिश की गई है।

अकील अहमद अंसारी ने लिखा कि कई विभागों में स्टाफ पॉलिटिक्स, चमचागिरी, गलत लोगों का प्रभाव, ईमानदार लोगों पर दबाव और ऊपर से नीचे तक दलाली जैसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। कई अधिकारी और कर्मचारी सच जानते हैं, लेकिन अकेले पड़ जाने या प्रताड़ना के डर से सामने नहीं आ पाते।

क्या है “गब्बर फाइल्स”?

“गब्बर फाइल्स” को एक “वैधानिक डिजिटल जनमंच” बताया गया है। इसके माध्यम से —आम जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगीmपीड़ित व्यक्ति अपनी बात और साक्ष्य साझा कर सकेंग,कर्मचारी और अधिकारी गोपनीय रूप से तथ्य उपलब्ध करा सकेंगे

दस्तावेज़ों और डिजिटल साक्ष्यों का प्रारंभिक सत्यापन किया जाएगा

वैधानिक और तथ्यात्मक जांच के बाद संबंधित विभागों को सक्रिय करने का प्रयास होगा

जनहित के मामलों को सार्वजनिक विमर्श तक पहुंचाया जाएगा

पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जो कर्मचारी और अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके अच्छे कार्यों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा, जबकि जनहित के खिलाफ कार्य करने वालों को दस्तावेज़ों और कानून के आधार पर जवाबदेह बनाने की कोशिश होगी।

पहचान गोपनीय रखने का दावा

इस पहल में शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखने की बात भी कही गई है। पोस्ट के अनुसार कोई व्यक्ति चाहे तो सीधे संपर्क कर सकता है या गोपनीय रूप से जानकारी साझा कर सकता है। हर स्थिति में उसकी पहचान सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह मंच किसी भी प्रकार की निजी हिंसा, धमकी, उगाही या गैर-कानूनी गतिविधि का समर्थन नहीं करेगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक मर्यादा के दायरे में संचालित करने का दावा किया गया है।

सोशल मीडिया पर मांगी जनता की राय

फेसबुक पोस्ट में लोगों से यह भी पूछा गया है कि क्या वे “सिस्टम में रहकर सिस्टम की सफाई” की शुरुआत चाहते हैं? क्या वे चाहते हैं कि केवल वायरल वीडियो नहीं, बल्कि डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जवाबदेही तय हो?

इसी के साथ लोगों से इस मुहिम पर अपनी राय देने और इसे अधिक से अधिक साझा करने की अपील की गई है।

पोस्ट के अंत में एक संदेश विशेष रूप से लिखा गया है —

“गब्बर फाइल्स — अब सच दबेगा नहीं दर्ज होगा।” - अकील अहमद अंसारी

जल जीवन मिशन में 15.50 लाख का फर्जीवाड़ा: परसदा योजना में कूटरचना, जांच रिपोर्ट ने खोला राज!

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़-बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़-बिलाईगढ़ क्षेत्र की परसदा (बड़े) ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन की नल-जल योजना पर भ्रष्टाचार का काला धब्बा लग गया है। लगभग 1 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना में फर्जी माप, अतिरिक्त प्रविष्टियां और नियमविरुद्ध हस्तांतरण के गंभीर आरोप लगे हैं। विभागीय जांच में ठेकेदार सरस गोयल द्वारा 15.50 लाख रुपये की फर्जी एंट्रीज उजागर हुईं। शिकायतकर्ता ने दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट जाने की धमकी दी है।

क्या कहती है जांच रिपोर्ट प्रमुख अनियमितताएं

RTI कार्यकर्ता और क्षेत्रीय पत्रकार गोपी अजय की शिकायत पर ऑनलाइन जनदर्शन से शुरू हुआ मामला अब प्रशासनिक जांच के केंद्र में है। 15 दिनों की जांच में माप पुस्तिका और वास्तविक कार्य के बीच भारी अंतर पकड़े गए:

चबूतरों में हेराफेरी: रिकॉर्ड में 342 चबूतरों का निर्माण दर्ज, लेकिन स्थल निरीक्षण में केवल 265 ही मिले – 77 चबूतरों का फर्जी दावा।

पाइपलाइन का भूत: 3500-4000 मीटर अतिरिक्त कम्पोजिट पाइपलाइन की प्रविष्टि, जो मौके पर बिल्कुल不存在। इससे 15.50 लाख की अतिरिक्त राशि का आहरण हुआ।

जल्दबाजी का हस्तांतरण: योजना पूरी तरह संचालित न होने पर भी 2 साल पहले कागजों में ₹पूर्ण₹ दिखाकर ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। भुगतान प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, बिना तकनीकी परीक्षण के।

संभावित और घोटाला: शिकायतकर्ता का दावा – विस्तृत जांच से 10 लाख तक की अतिरिक्त अनियमितताएं सामने आ सकती थीं। जांच रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी गई है, जिसमें राशि वसूली की सिफारिश की गई। प्रारंभिक शिकायत को बिना स्थल निरीक्षण ठेकेदार के पक्ष में बंद कर दिया गया था, लेकिन अपील और मीडिया कवरेज के बाद नई टीम गठित हुई।

जनता के करोड़ों लुटे, अपूर्ण कार्य को पूरा बताकर हस्तांतरित – शिकायतकर्ता हाईकोर्ट की चेतावनी

शिकायतकर्ता का आरोप: मिलीभगत और कूटरचना का खेल

गोपी अजय ने कहा, ₹यह तकनीकी त्रुटि नहीं, सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी है। मेरा बयान जांच में नहीं लिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार के बीच सांठगांठ साफ दिख रही। अपूर्ण कार्य को पूरा बताकर भुगतान निकालना और रिकॉर्ड गढ़ना दंडनीय अपराध है।₹ उन्होंने उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच, FIR और विभागीय कार्रवाई की मांग की। अगर 15 दिनों में कदम न उठे, तो हाईकोर्ट में PIL दायर करेंगे।

ग्रामीणों का दर्द: पानी का वादा अधर में, गुस्सा फूटा

ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। एक स्थानीय निवासी ने बताया, ₹योजना का मकसद था हर घर में नियमित स्वच्छ पानी, लेकिन आज तक ठीक से चले ही नहीं। करोड़ों खर्च कर लूट ली गई।₹ योजना का उद्देश्य विफल होने से पेयजल संकट गहरा गया है। लोग जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।

बड़ा सवाल: कार्रवाई कब?

लाखों की चोरी साबित होने पर भी अधिकारी चुप्पी साधे हैं। क्या यह मामला ठंडे बस्ते में जाएगा? या कलेक्टर रिकवरी के साथ-साथ आपराधिक केस दर्ज करेंगे? जनता की नजरें प्रशासन पर टिकी हैं। जल जीवन मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत है।

भटगांव में सुखाड़ पुल ध्वस्त: एस-ईसीएल की लापरवाही से करोड़ों का नुकसान, बड़ा हादसा टला

न्यूज रुटीन @ सरगुजा भटगांव

एसईसीएल भटगांव क्षेत्र के महान-3 जाने वाले जगरनाथपुर-खड़-गवां मार्ग पर स्थित सुखाड़ पुल कल देर रात बीचों-बीच से टूट गया। पुल ध्वस्त होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और एसईसीएल का कोयला परिवहन भी रुक गया, जिससे प्रतिदिन करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना रात करीब 11 बजे हुई। उस वक्त पुल पर दोनों ओर से वाहन आ-जा रहे थे। गनीमत रही कि चालक समय रहते रुक गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, कुछ सेकंड की देरी होती तो कई जिंदगियां दांव पर लग जातीं। ग्रामीणों, मजदूरों और कर्मचारियों ने एसईसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पुल लंबे समय से जर्जर था। गड्ढे और दरारें बार-बार उभरती रहीं, लेकिन स्थायी मरम्मत या नया पुल बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

हर बार अस्थायी पैचवर्क कर मामला दबा दिया जाता रहा

लोगों ने याद दिलाया कि इसी पुल पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें मौतें भी हुईं। जिम्मेदारों ने सबक नहीं लिया। कार्यवाही के नाम पर केवल लीपापोती हुई और मजदूरों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया। एक ग्रामीण ने सवाल किया, ₹रोज करोड़ों कमाने वाली कंपनी कर्मचारियों और ग्रामीणों की जान की परवाह क्यों नहीं करती? हम सालों से जान जोखिम में डालकर पार होते रहे। पुल टूटने से महान-3 क्षेत्र का संपर्क कट गया। कोयला उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन वैकल्पिक मार्ग तथा जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर भारी आक्रोश है। लोग मांग कर रहे हैं—तत्काल नया पुल बने और दोषियों पर कार्रवाई हो।

अवैध साल लकड़ी परिवहन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर। वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साल लकड़ी से भरे एक पिकअप वाहन को जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई बलरामपुर डीएफओ आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देशन एवं उपवनमण्डलाधिकारी अनिल कुमार सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 मई 2026 को वनपरिक्षेत्र बलराम-पुर के सर्किल मानिकपुर अंतर्गत बीट मानिकपुर के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 3511 वनखण्ड मानपुर में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 टी 9601 को पकड़ा। वाहन में साल प्रजाति के 08 नग लट्ठे, कुल 1.915 घनमीटर लकड़ी अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी।

मामले में विष्णु गुप्ता पिता स्व. दशरथ गुप्ता एवं सर्वोत्तम गुप्ता पिता विष्णु गुप्ता, निवासी ग्राम बानापती थाना रामानुजगंज जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के खिलाफ वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21979/12 दिनांक 11 मई 2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं 52 तथा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 के नियम 22 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पूछता है सारगढ़ , डबल इंजन की सरकार क्या करेगी सपनो को साकार कब पूरी होगी हमारी मांग

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़।

सारंगढ़ के निवासियों के दो प्रमुख सपने थे—एक तो जिले का दर्जा पाना और दूसरा रेलवे लाइन की सौगात। पहला सपना पूरा हो चुका है, अब दूसरा सपना कब साकार होगा? प्रदेश की डबल इंजन सरकार से बड़ी उम्मीदें बंधी हैं।

एक दिन सारंगढ़ के प्रसिद्ध पेंटर और स्व. किशोर कुमार के प्रखर प्रशंसक भगत गुप्ता कागजों से भरी थैली लिये मशहूर अधिवक्ता विजय कुमार तिवारी के पास पहुंचे। विजय जी वर्तमान सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। भगत गुप्ता ने दुखी स्वर में कहा, ₹महाराज जी, नमस्कार! ये देखिए कागजात... ये रेलवे लाइन के लिए हैं। क्या इन पत्रों, नेताओं की घोषणाओं और शासन के आदेशों के आधार पर न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं?

विजय तिवारी ने उन्हें समझाया, ₹गुप्ता जी, अदालत अंतिम रास्ता है। पहले क्षेत्रीय नेता, विधायक, सांसद और मंत्री से मिलें। वे आपकी मांग पूरी करवा सकते हैं।₹ भगत जी ने थकान भरे लहजे में जवाब दिया, ₹महाराज जी, मैं थक चुका हूं। बलौदा बाजार से सारंगढ़ होते हुए झारसुगुड़ा तक रेल मार्ग बजट में आया था, लेकिन अब स्थगित बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था, तब से मैं दौड़-भाग कर रहा हूं। नेताओं ने लिखा भी—विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है!

भगत गुप्ता ने खुद खर्च कर पढ़ाई की और दस्तावेज जमा किए, लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। फिर भी, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार है। सारंगढ़ के पूर्व सांसद और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की भूमिका यहां अहम हो सकती है। उनकी इच्छाशक्ति से यह सपना सच हो सकता है। अब देखना है—क्या सारंगढ़ में रेल की पटरी बिछेगी या सपना फिर अधूरा रहेगा?

सारंगढ़ वासी उम्मीद भरी नजरों से केंद्र और राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं। बलौदा बाजार-सारंगढ़-झारसुगुड़ा रेल परियोजना पर जल्द फैसला हो, यही मांग है।

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने ली विभिन्न विभागों की मैराथन बैठक

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं के प्रगति का समीक्षा किया। कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा, पीएम आवास, पूर्ण आवास, शेष आवास निर्माण, किश्त मिलने पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने वाले हितग्राही को नोटिस देना और कार्य नहीं करने पर सरकारी राशि का वसूली प्रक्रिया आदि के बारे में कलेक्टर ने जिले के सभी सीईओ से चर्चा

किया।इसी प्रकार निर्माण एजेंसी लोक निर्माण, पीएमजीएसवाय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, गृह निर्माण मण्डल, जल संसाधन विभाग, नगरीय निकाय द्वारा जिले में किये जा रहें जिसमें पीडब्लूडी द्वारा जिला सयुंक्त कार्यालय, सीजीएमएससी द्वारा जिला अस्पताल, सीएमएचओ कार्यालय, पीएचई द्वारा जल जीवन मिशन, मल्टीविलेज, सारंगढ़ और बरमकेला में जल आवर्धन, नगर पंचायत सरिया द्वारा सरिया में अमृत मिशन 2.0, नगरपालिका सारंगढ़ द्वारा नालंदा लाइब्रेरी, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा सेजेस स्कूल निर्माण, जल संसाधन विभाग द्वारा लात नाला निर्माण, नहर मरम्मत आदि के लक्ष्य, उपलब्धि और प्रगति की रिपोर्ट के बारे में चर्चा किया गया। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के ईकेवायसी.

विधानसभा स्तरीय मासिक बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं जुटे

छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस सरकार बनाने कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प

न्यूज रुटीन @ बिलाईगढ़

सामुदायिक भवन बिलाईगढ़ में सरसीवा, बिलाईगढ़ एवं सोनाखान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में विधानसभा स्तरीय मासिक बैठक का भव्य आयोजन किया गया। बैठक में बिलाईगढ़ विधानसभा की विधायक कविता प्राण लहरें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया।बैठक में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी को सक्रिय करने, आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने तथा आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी चुनाव में छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया। विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरें जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं एवं गरीब वर्ग के हितों के लिए संघर्ष करती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की जनहितकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आज भी याद करती है तथा आने वाले समय में प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ मैदान में जुट जाएं।उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर आम जनता से संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं को सुनने एवं कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने का आह्वान किया। विधायक ने कहा कि संगठन की असली ताकत कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं समर्पण से ही पार्टी को मजबूती मिलती है। बैठक में क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों एवं आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पेंटर शिवकुमार निराला ने कलेक्टर को भेंट किया जिले का राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र

सारंगढ़.सारंगढ़ कलेक्ट्रेट में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम चकरदा निवासी पेंटर शिवकुमार निराला ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले अनूठा राजनीतिक, भौगोलिक मानचित्र को कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू को भेंट किया। उनकी इस अद्वितीय पेंटिंग कला प्रस्तुति ने कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बढ़ा दिया। पेंटर निराला द्वारा तैयार एक मानचित्र 3 माह में तैयार किया गया है, जिसमें कुल गांव, वीरान गांव, डेम, सड़क आदि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कलेक्टर ने इनके कलाकृति और सराहनीय कार्य का विस्तृत अवलोकन किया और उनके कार्य की तारीफ की।

सुशासन तिहार शिविर में नागरिकों सुविधाओं का अम्बार

सुशासन शिविर में तत्काल बनाया गया आयुष्मान, आयुष्मान वय वंदन, राशन कार्ड, आधार कार्ड और ई-श्रम कार्ड

एग्रीस्टेक पंजीयन, महतारी वंदन योजना का ई-केवाईसी और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी शिविर में उपलब्ध

सुशासन के हिर्री शिविर में 20 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने लिया हिस्सा

न्यूज रुटीन @ सारंगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी 'सुशासन तिहार 2026' अब जनविश्वास का महाअभियान बन चुका है। इसी कड़ी में गुरुवार को बरमकेला विकासखंड के ग्राम पंचायत हिर्री में आयोजित क्लस्टर स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में जिला प्रशासन सीधे ग्रामीणों के पास पहुँचा। शिविर में 20 ग्राम पंचायतों के हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया, जहाँ कुल 505 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू,सत्ताधारी दल के वरिष्ठ राजनीतिक सदस्य जगन्नाथ पाणिग्राही, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत वर्मन एसडीएम वर्षा बंसल सहित प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा बारी बारी से योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई।

शिविर की प्रमुख उपलब्धियां और त्वरित सेवाएं

सुशासन तिहार शिविर में नागरिकों को सुविधाओं का अम्बार प्राप्त हो रहा है। हिर्री में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर मौके पर ही एग्रीस्टैक पंजीयन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड और महतारी वंदन योजना की ई-केवाईसी जैसी सुविधाएं तत्काल प्रदान की गईं।आयुष्मान कार्ड और वय वंदन कार्ड निर्माण के साथ-साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

हितग्राहियों को मिली राहत की सौगात

शिविर में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, जगन्नाथ पाणिग्राही, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय नायक, सदस्य अभिलाषा नायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ देते हुए सामग्री, कार्ड आदि वितरित किया गया। शिविर में कलेक्टर एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत शिशुओ को अन्न प्रासन्न एवं गर्भवती महिलाओं का गोदभराई कर उन्हें सुपोषण टोकरी प्रदान किया गया।

व्यवहार न्यायालय बिलाईगढ़ में अधिवक्ता संघ को विधायक कविता प्राण लहरें की बड़ी सौगात

न्यूज रुटीन @ बिलाईगढ़

व्यवहार न्यायालय बिलाईगढ़ में अधिवक्ता संघ द्वारा आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हुए अधिवक्ता संघ बिलाईगढ़ को 2 ए.सी. भेंट स्वरूप प्रदान किए। साथ ही अधिवक्ता संघ की लायब्रेरी के विकास के लिए 1 लाख की सहयोग राशि देने की घोषणा की। विधायक की इस पहल का अधिवक्ता साथियों ने स्वागत

विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरें शामिल हुईं। इस दौरान अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ता साथियों द्वारा विधायक का आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरें ने अधिवक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते करते हुए आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय बिलाईगढ़ में नवपदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सिद्धांत देवांगन जी का अधिवक्ता संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरें ने उन्हें शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी समाज के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरें ने अपने उद्बोधन में कहा कि अधिवक्ता समाज न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग है। आम जनता को न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उनके लिए बेहतर कार्य वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ की लायब्रेरी को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख की राशि की घोषणा की गई है, जिससे अधिवक्ताओं को अध्ययन सामग्री एवं विधि संबंधी पुस्तकों की सुविधा मिल सके।

कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ता साथियों के साथ सामाजिक, न्यायिक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा भी हुई। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, अधिवक्ता साथी, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरें ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों का स्नेह एवं विश्वास उन्हें सदैव जनसेवा के लिए प्रेरित करता है।

पैतृक भूमि पर जबरन कब्जे का आरोप, पीड़ित ने जनदर्शन में लगाई न्याय की गुहार

बिलासपुर/मस्तूरी। मस्तूरी तहसील अंतर्गत ग्राम बेदपरसदा में पैतृक भूमि पर कथित अवैध कब्जे और जबरन मकान निर्माण का मामला सामने आया है। ग्राम निवासी रविनंदन उर्फ रवि कैवर्त ने जिला कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आवेदक रविनंदन कैवर्त ने बताया कि ग्राम बेदपरसदा प.ह.न. 12 स्थित उनकी पैतृक भूमि खसरा नंबर 162/1 रकबा 1.76 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। आरोप है कि गांव की ही अनिता बाई, पुनीता बाई, सुकिता बाई एवं सरिता बाई द्वारा लगभग 50 डिसमिल जमीन पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण किया जा रहा है।पीड़ित ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई तथा राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से उनकी भूमि हड़पने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि तहसीलदार मस्तूरी के समक्ष स्थगन आदेश के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। रविनंदन कैवर्त का कहना है कि वे अशिक्षित हैं और पटवारी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। उन्होंने जिला प्रशासन से अवैध निर्माण तत्काल रुकवाने और निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है तथा अब लोगों की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है।

सुशासन तिहार में दंडवत गुहार : आवास की मांग ने खोली जमीनी हकीकत

सुशासन तिहार के दौरान गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड में एक ऐसा भावुक दृश्य सामने आया, जिसने प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर कर दिया।

न्यूज रुटीन @ गरियाबंद

देवभोग विकासखंड के माड़ागांव में आयोजित कार्यक्रम में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार समाज के कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग को लेकर जिला पंचायत सीईओ के सामने दंडवत होते नजर आए। किसी ने पैर पकड़कर अपनी पीड़ा व्यक्त की तो कुछ लोग जमीन पर लेटकर सहायता की गुहार लगाते दिखे। इस दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया।

जानकारी के अनुसार, बरही गांव में रहने वाले कमार जनजाति के परिवार लंबे समय से आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे जर्जर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जहां बरसात के दिनों में छत टपकती है और असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। कई बार आवेदन देने और पंचायत से लेकर जनपद स्तर तक समस्या रखने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सका।

कार्यक्रम के दौरान जब अधिकारी समस्याएं सुन रहे थे, तभी ग्रामीण अचानक सामने पहुंच गए और मदद की गुहार लगाने लगे। उनका आरोप है कि पात्र होने के बावजूद उन्हें योजना की सूची में शामिल नहीं किया गया। इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक व्यवस्था और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कमार समाज को अत्यंत संवेदनशील और विशेष संरक्षण योग्य जनजाति माना जाता है। ऐसे में इस समुदाय के लोगों को बुनियादी सुविधा के लिए इस तरह गुहार लगानी पड़े, तो यह व्यवस्था की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर सवाल उठाए।

प्रशासन की ओर से मामले की जांच कराने और पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित परिवारों के दस्तावेजों की समीक्षा कर पात्र पाए जाने पर उन्हें जल्द आवास योजना से जोड़ा जाएगा।

दंडवत गुहार ने झकझोरा सिस्टम

सुशासन तिहार जैसे कार्यक्रम में कमार जनजाति के परिवारों का अधिकारियों के सामने दंडवत होना यह दर्शाता है कि अब भी कई जरूरतमंद परिवार योजनाओं से वंचित हैं। यह दृश्य प्रशासनिक दावों और जमीनी स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर को सामने लाता है।

आश्वासन और सवाल दोनों कायम

प्रशासन ने जांच कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की बात कही है, लेकिन घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में अंतिम व्यक्ति तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।

दुष्कर्म व हत्या के दोषी की मृत्यदंड की सजा उम्र कैद में तब्दील

बिलासपुर। महिला को बहलाकर जंगल ले जाकर दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी की मृत्युदंड की सजा को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा में तब्दील कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बड़ी सजा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दी जा सकती है. जहां यह सख़्त लिमिट पूरी नहीं होती, वहां मौत की सजा को उम्रकैद में बदलना जरूरी है. इसके साथ यह भी निर्देश दिया कि ऐसी उम्रकैद दोषी की पूरी जिंदगी तक जारी रहेगी. मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीबी ने यह फैसला सुनाया है.

बता दें कि बेमेतरा परिवार न्यायालय में भृत्य के पद में कार्यरत 25 वर्षीय महिला 9 अगस्त 2022 को छुट्टी पर अपने गांव खैरमुड़ा आई थी. 14 अगस्त 2022 को सुबह करीब 9 बजे, वह अपनी स्कूटी से अपने घर से निकली और अपने परिवार वालों को बताया कि वह बेमेतरा जा रही है. वह अपनी मंज़िल तक नहीं पहुंची और उसका पता नहीं चला. उसके परिवार वालों की कोशिशों और रिश्तेदारों और गांव वालों से पूछताछ के बावजूद पीड़िता का कोई पता नहीं चल सका.15 अगस्त 2022 को उसके पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस स्टेशन डभरा में गुमशुदा तौर पर रजिस्टर किया. पूछताछ के दौरान आरोपी पर शक हुआ, जो पीड़ित को जानता था. पीड़ित के पिता और मृतक की छोटी बहन के बयानों से पता चला कि आरोपी मोबाइल फोन पर पीड़ित के साथ रेगुलर संपर्क में था. इस आधार पर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की गई. सीसीटीवी फुटेज समेत इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर, जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन के तहत सर्टिफिकेट से सपोर्टेड थे.साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने आरोपी शंकर निषाद निवासी गाँव सुखदा, पुलिस स्टेशन डभरा, जिला सक्ति को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मृतका से संपर्क में रहा. घटना दिनांक को उसने फोन कर उसे बुलाया एवं बरसात के कारण रास्ता बंद होने की बात कही और नया रास्ता बताने की बात कहते हुए उसे खरसिया स्टेशन लेकर गया, जहां अपनी मोटर साइकिल रेलवे स्टेशन के पार्किंग में पार्क कर मृतका की एक्टिवा में पालगड़ घाटी ले गया.यहां स्कार्फ में उसके हाथ बांध कर पहले दुष्कर्म किया, उसके बाद ब्लेड से हाथ व गले की नस काटकर हत्या की. पुलिस ने उसके मेमोरडंम पर जंगल से शव बरामद किया एवं पीएम कराया. इस मामले में जांजगीर एफटीसी कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई. सजा की पुष्टि के लिए शासन ने हाई कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया. वहीं आरोपी ने भी हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि आरोपी को दी गई मौत की सजा रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती है, इसलिए कानून में टिकने लायक नहीं है. इसे आरोपी की बाकी जिंदगी के लिए उम्रकैद में बदला जाता है.

भाजपा का नया कोर ग्रुप करता है कुछ इशारे, ओपी चौधरी का नाम आना बड़ा संदेश, अमर की भी एंट्री

न्यूज रुटीन @ रायपुर

भाजपा ने कोरग्रुप की बैठक बुलाई तो इसमें शामिल बड़े दिग्गजों को इसकी सूचना ही नहीं भेजी गई। इसके बाद बैठक हुई तो पता चला कि कोरग्रुप ही बदल दिया गया है। इस बदलाव के पीछे काफी समीकरण और अगले विधानसभा चुनाव के प्लान के इशारे दिखते हैं। भाजपा में कोरग्रुप का बड़ा स्थान है, क्योंकि सारे संगठनात्मक फैसले यहीं होते हैं और नीतियां यहीं तय होती हैं।

सबसे वरिष्ठ और धाकड़, अपराजेय माने वाले पुन्नुलाल मोहले को भी ग्रुप से बाहर किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अब संगठन नई पीढ़ी को जगह देकर लीडरशिप की लाइन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके पीछे न केवल आगामी विधानसभा चुनाव, बल्कि लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद शीर्ष नेतृत्व पूरे आत्म विश्वास में है और हर राज्य में इस तरह के बदलाव भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल को भी कोर ग्रुप में नहीं रखा गया है, चर्चा है कि इससे पार्टी में भीतर ही भीतर हलचल हो सकती है। राज्य बनने के बाद से लगातार कोरग्रुप में रहने वाले बृजमोहन को बैठक

की सूचना तक नहीं दी गई थी। जबकि राज्य गठन के बाद पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल का भी नाम कोर ग्रुप में नहीं है। इसी तरह मंत्रिमंडल से रामविचार नेताम को कोरग्रुप से बाहर कर वित्त मंत्री ओपी चौधरी को स्थान दिया गया है। चौधरी का नाम कोरग्रुप में आना बड़ा संदेश दे रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के दौरान रायगढ़ में चुनावी सभा में ओपी चौधरी की पीठ थपथपा कर कहा था कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। यह अब साकार होता दिख रहा है।

राजिम में नदी, है या मैदान..! बिगड़ता जा रहा त्रिवेणी संगम का स्वरूप

न्यूज रुटीन @ राजिम

छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम त्रिवेणी संगम की नदियों का स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में लगातार बदलता जा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो यहां नदी कम और भाठा अर्थात मैदान अधिक दिखाई दे रहा हो। विशेष रूप से कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर से पैरी और सोंढूर नदी की ओर हालात अत्यंत चिंताजनक हो चुके हैं। यहां नदी के तल में रेत कम और मिट्टी की मोटी परत अधिक जमा हो गई है, जिसमें छोटे-बड़े घास और अनेक पौधे उग आए हैं।नवागांव एनीकेट के दोनों ओर, एक तरफ त्रिवेणी संगम तथा दूसरी ओर नवीन मेला मैदान से लेकर चौबेबांधा पुल के आगे तक स्थिति गंभीर बनी हुई है। विभिन्न स्थानों पर मिट्टी के बड़े-बड़े टीले खड़े हो गए हैं। अब नदी का तल समतल नहीं रह गया है, बल्कि कहीं ऊंचा तो कहीं गहरा दिखाई देता है।

उल्लेखनीय है कि यही नदी दो दशक पहले तक स्वच्छ और निर्मल हुआ करती थी। नदी के तल में दूर-दूर तक केवल साफ रेत दिखाई देती थी। लोग बताते हैं कि उस समय नदी में पैर रखते ही सारी गंदगी साफ हो जाती थी, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि स्वच्छ पैर भी नदी में रखने पर गंदे हो जाते हैं।

इस विषय पर स्थानीय लोगों से चर्चा करने पर भागवत, युवराज, भेषज, रघुनाथ और मंथीर ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से नदी से रेत परिवहन का गोरखधंधा चल रहा है। उनका आरोप है कि रेत कारोबारियों की पहुंच मंत्री से लेकर संतरी तथा अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक है। यही कारण है कि नदी का लगातार दोहन हो रहा है और इसे कमाई का जरिया बना लिया गया है, चाहे नदी का अस्तित्व ही क्यों न खतरे में पड़ जाए।

वहीं नदी किनारे मौजूद विनय, रामकृष्ण, राकेश, मनोज और दीनबंधु ने कहा कि यह नदी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। उनका कहना है कि सोंढूर, पैरी और महानदी त्रिवेणी संगम से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तक रेत उत्खनन पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में शहर सहित आसपास के सैकड़ों गांवों को पानी की एक-एक बूंद के लिए भटकना पड़ सकता है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले इसी नदी में पूरे वर्ष पानी की धार बहती रहती थी, लेकिन अब जनवरी माह में ही जलस्तर नीचे चला जाता है और पानी का प्रवाह लगभग बंद हो जाता है। मेला अवधि में सिकासेर जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद ही नदी में जल दिखाई देता है।

क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि नदी की रेत ही पानी को संजोकर रखने का काम करती है। अब जब नदी से रेत लगातार खत्म हो रही है, तो पानी का संरक्षण भी संभव नहीं रह गया है। लोगों ने प्रशासन से समय रहते ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए नदी और जलस्रोतों को बचाया जा सके।

छत्तीसगढ़ की जीवनदायनी महानदी का भी यही हाल

महानदी भी अब भाठा का स्वरूप ले चुकी है। बेलाही पुल के नीचे दोनों ओर मैदान में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। वहां मिट्टी की मोटी परत स्पष्ट नजर आती है। इसके अलावा महानदी पुल के नीचे की स्थिति भी इसी कहानी को बयां कर रही है।मिली जानकारी के अनुसार, कुछ वर्ष पहले मेला बैठक के दौरान एक मंत्री ने संगम क्षेत्र को बचाने के लिए आसपास कम से कम पांच किलोमीटर तक रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, लेकिन यह निर्णय केवल बैठकों तक ही सीमित रह गया। बताया जाता है कि वर्षभर पहले राजिम सर्किट हाउस में नदी बचाने को लेकर कई बैठकें आयोजित की गई थीं और समिति का भी गठन किया गया था, लेकिन अब तक उसकी कार्यशैली धरातल पर दिखाई नहीं दी है।

जमीन तो दूर सीपत के श्मशान भी सुरक्षित नहीं

जहाँ अवैध कब्जाधारी ने सिर्फ निर्माण कराया बल्कि कुछ दिन पहले दफनाए गए मृतक की कब्र पर भी जेसीबी चलवा दिया

न्यूज रुटीन @ बिलासपुर

सीपत में बेजा कब्जाधारियों का बेखौफ आतंक दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है। सड़क किनारे की जमीन हो या दूसरी सरकारी भूमि, हर तरफ कब्जे की होड़ मची हुई है। 13मई को नवाडीह बस्ती के पीछे स्थित सर्व हिंदू समाज के श्मशान घाट की सरकारी भूमि तक नहीं बच पाया है, जहां अवैध कब्जाधारी ने न सिर्फ निर्माण कराया बल्कि कुछ दिन पहले दफनाए गए मृतक की कब्र पर भी जेसीबी चलवा दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।प्राप्त के अनुसार, सीपत ग्राम पंचायत के खसरा नंबर 967 दाह संस्कार के लिए भूमि आरक्षित की गई है, जहां कई वर्षों से शव दफनाए जाते रहे हैं। इसी भूमि से लगे क्षेत्र में बिल्हा विकासखंड के ग्राम रामपुर ढोढ़ी निवासी रामखिलावन पटेल ने करीब 7 वर्ष पूर्व खसरा नंबर 938 रकबा 2.43 हेक्टेयर (60 डिसमिल) एवं खसरा नंबर 867/3 रकबा 15 डिसमिल कुल 75 डिसमिल जमीन खरीदी थी। खरीदी गई भूमि पर उसने पोल्ट्री फार्म और सब्जी बाड़ी तैयार की, लेकिन बाद में श्मशान घाट की सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर भव्य दो मंजिला मकान खड़ा कर दिया। और वहां पर लगभग 2 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है।

ग्रामीणों के लगाया आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि मकान निर्माण के दौरान कई बार पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उसे श्मशान घाट की भूमि खाली करने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। हालात तब और गंभीर हो गए जब कुछ सप्ताह पहले ही दफन किए गए 62 वर्षीय रामकुमार सूर्यवंशी की कब्र को जेसीबी से समतल कर वहां तार फेंसिंग कर कब्जा कर लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बुधवार सुबह जनपद पंचायत सभापति मनोज खरे, सरपंच प्रतिनिधि योगेश वंशकार, द्वारिका प्रसाद खरे, लच्छी वर्मा, पोषण सत्यार्थी, दिनेश विजय सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया।जनपद पंचायत सभापति मनोज खरे ने कहा कि श्मशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित व्यक्ति के पास केवल 60 डिसमिल जमीन है, लेकिन उसने करीब 2एकड़ से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत प्रशासन से कर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी और वहां से बेजा कब्जा हटाई जाए।

कफ़न दफन की भूमि भी सुरक्षित नहीं, हटाई जाएगी बेजा कब्जाधारी,,, योगेश वंशकार

सरपंच प्रतिनिधि योगेश वंशकार ने कहा कि इन दिनों सीपत में बेजा कब्जाधारियों की बाढ़ सी आ गई है। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकारी जमीनों के साथ श्मशान घाट में दफन मुर्दे भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। पंचायत और प्रशासन स्तर पर जल्द कार्रवाई के लिए पहल की जाएगी।

श्मशान की भूमि जल्द खाली कराई जाए, और प्रशासन कड़ी कार्यवाही करें,, द्वारिका खरे-सीपत के ग्रामीण द्वारिका प्रसाद खरे ने आक्रोश जताते हुए कहा कि श्मशान घाट की जमीन को हर हाल में कब्जामुक्त कराया जाएगा। जरूरत पड़ी तो अवैध रूप से बने दो मंजिला मकान को हटाने की भी मांग की जाएगी, क्योंकि यह गांव की सार्वजनिक भूमि है और यहां किसी को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जांच कर कब्जा हटाने, श्मशान घाट को सुरक्षित रखने एवं दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है।

CM विष्णुदेव साय ने भी काफिले से गाड़ियां घटाई, पीएम मोदी की अपील का दिखने लगा असर

रायपुर

पीएम मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ सीएम ने अपने सरकारी काफिले का आकार कम करने और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की घोषणा की है। एम नरेंद्र मोदी की वर्क फ्रॉम होम और ईंधन की बचत वाली अपील का असर दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए अपने सरकारी काफिले का आकार कम करने और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की घोषणा की है। उन्होंने अपने मंत्रियों और विभिन्न सरकारी निगमों व बोर्डों के पदाधिकारियों से भी सरकारी संसाधनों और वाहनों का संयमित उपयोग करने की अपील की है।

यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने ईंधन की बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात कही थी। पीएम मोदी ने हाल ही में पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग, कारपूलिंग बढ़ाने, रेलवे से पार्सल ढुलाई को प्राथमिकता देने और जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी थी। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पश्चिम एशिया का संघर्ष पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है और भारत भी इससे प्रभावित है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह आह्वान बेहद महत्वपूर्ण है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष ध्यान देंगे-उन्होंने कहा, "हमने भी इस अपील का पालन किया है। हमने अपने सरकारी काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में ठोस

कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों से भी संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की अपील की गई है। सीएम साय ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा कि वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों के इस दौर में पेट्रोल-डीजल जैसे संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बदलावों से बड़ा परिवर्तन संभव है।

लोगों से अपील-उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग को अपनाएं और निजी वाहनों का अनावश्यक इस्तेमाल कम करें। साथ ही उन्होंने कहा कि "राष्ट्र प्रथम" की भावना के साथ ईंधन बचत को जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी कहा था कि वे सुरक्षा कारणों को छोड़कर अपने काफिले में पायलट और फॉलो वाहनों का उपयोग कम करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री की अपील का पालन किया जा सके।

मंत्री-विधायक भी दिखे सादगी के अंदाज में-प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में भी इस बदलाव की झलक देखने को मिली। कई मंत्री और विधायक बिना बड़े काफिले के कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के साथ पदाधिकारी एक ही वाहन में बैठकर पहुंचे। यहां तक कि पार्टी के कुछ प्रवक्ता भी ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करते नजर आए। भाजपा इसे "सकारात्मक और जिम्मेदार राजनीति" का संदेश बता रही है।

बीजेपी बोली - सकारात्मक बदलाव की शुरुआत-डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का असर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली में दिख रहा है और इससे जनता के बीच भी ईंधन संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे भविष्य के लिए जरूरी कदम बताया।

कांग्रेस का पलटवार, भ्रष्टाचार पर घेरा-दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर सियासी हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सिर्फ काफिले कम करने से पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी।

कांग्रेस का आरोप है कि यदि वास्तव में आर्थिक सुधार करना है तो सरकार को पहले भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और फिजूलखर्ची पर रोक लगानी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि यह कदम केवल "राजनीतिक संदेश" भर है, जिससे आम लोगों को सीधी राहत नहीं मिलने वाली।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस-पीएम मोदी की अपील के बाद छत्तीसगढ़ में अब नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। भाजपा इसे आर्थिक अनुशासन और जिम्मेदार प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे दिखावटी राजनीति करार दे रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी काफिलों में कटौती और ईंधन बचत जैसे कदम आम नागरिक को महंगाई और आर्थिक दबाव से राहत दिला पाएंगे, या फिर यह केवल एक अल्पकालिक राजनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा।

जो मां कभी नहीं थकती, वही बच्चों के सपनों को उड़ान देती है

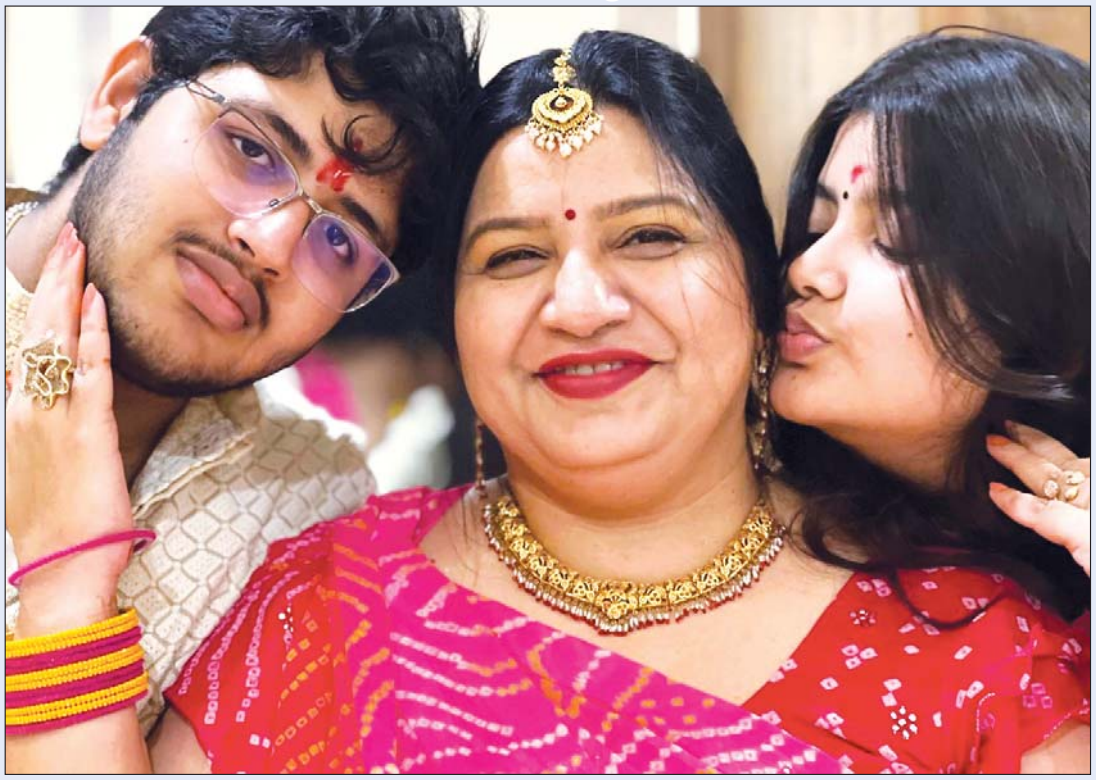

रायपुर। मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वह त्याग, संघर्ष, जिम्मेदारी और प्रेरणा का ऐसा रूप होती है जो हर परिस्थिति में अपने परिवार के लिए मजबूती बनकर खड़ी रहती है। मदर्स डे के अवसर पर ऐसा ही भावुक दृश्य देखने को मिला जब आदित्य राज सिंह अपनी मां नम्रता सिंह से मिलने मुंबई से रायपुर पहुंचे और भावुक होकर कहा — हमारी मां जैसा कोई नहीं। आदित्य राज सिंह वर्तमान में मुंबई में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि उनकी बहन आरना सिंह का चयन लंदन के प्रतिष्ठित किंग्स कॉलेज में हो चुका है और वह अगले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए लंदन रवाना होंगी।

सुबह 5 बजे से शुरू होती है मां की जिम्मेदारियां-आदित्य बताते हैं कि उनकी मां का दिन दूसरों की सेवा से शुरू होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी स्वास्थ्य शिविर आयोजित होते हैं, उस दिन भी नम्रता सिंह सुबह 5 बजे उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता और बच्चों का टिफिन तैयार करती हैं। दिनभर सामाजिक कार्यों और स्वास्थ्य शिविरों में व्यस्त रहने के बाद भी शाम को घर लौटकर बच्चों की पसंद का खाना बनाना नहीं भूलतीं।

उन्होंने कहा कि इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मां ने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह थक गई हैं।

दूसरों की सेवा में मिलता है आत्मिक सुख-वहीं आरना सिंह कहती हैं कि उनकी मां हमेशा एक ही बात कहती हैं — दूसरों की सेवा करने से जो आत्मिक सुख मिलता है, वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। शायद यही वजह है कि आज उनके बच्चे भी सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं।

आरना बताती हैं कि सामाजिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने के बावजूद उनकी मां ने घर और बच्चों की जिम्मेदारियों को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में परिवार और समाज दोनों के बीच अद्भुत संतुलन बनाया।

आईपीएस बनने का सपना, लेकिन समाज सेवा नहीं छोड़ी-कम ही लोग जानते हैं कि नम्रता सिंह कभी लखनऊ में आईपीएस की तैयारी कर रही थीं। उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज के लिए काम करना था। लेकिन एक मध्यमवर्गीय परिवार की बेटी की तरह जीवन ने नया मोड़ लिया और उनका विवाह डॉक्टर डॉ विनोद सिंह के साथ हो गया। शादी के बाद परिवार, बच्चों और उनके भविष्य की जिम्मेदारियों ने जीवन को नया आकार दिया, लेकिन समाज सेवा का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। इसी सोच ने आगे चलकर उर्मिला फाउंडेशन की नींव रखी।

ग्रामीण स्वास्थ्य जागरूकता को बनाया मिशन-नम्रता सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी को करीब से महसूस किया। इसके बाद उन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना शुरू किया। भाटा गांव स्थित उर्मिला हॉस्पिटल में लगातार निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कई ऐसी महंगी जांचें, जो ग्रामीण परिवारों के लिए संभव नहीं होतीं, उन्हें फाउंडेशन के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक मां, जिसने परिवार और समाज दोनों को संभाला-आज नम्रता सिंह के अथक प्रयासों का परिणाम है कि उनके बच्चे देश और विदेश में सफलता का परचम लहरा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वह एक जिम्मेदार मां के साथ-साथ समाज के प्रति अपने दायित्व को भी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। मदर्स डे पर उनकी कहानी यह संदेश देती है कि मां कभी हार नहीं मानती। वह हर दिन अपने परिवार, अपने बच्चों और समाज के बेहतर भविष्य के लिए बिना रुके आगे बढ़ती रहती है

बस्तर की इमली का स्वाद चख बोले अमित शाह – यहां की इमली खट्टी नहीं, मीठी है

बस्तर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नेतानार ग्राम में जनसुविधाओं के विस्तार और महिला सशक्तिकरण की पहल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बस्तर की इमली का स्वाद चखा और उसकी मिठास की सराहना की।

जगदलपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को बस्तर जिले के नेतानार ग्राम स्थित सीआरपीएफ कैम्प पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा (जन सुविधा केंद्र) का उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न ऑनलाइन और सरकारी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं।

दौरे के दौरान उन्होंने इमली प्रसंस्करण केंद्र का निरीक्षण किया और स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने बताया कि वे इमली प्रसंस्करण के जरिए अपनी आय बढ़ा रही हैं। समूह की सदस्य लंबी नाग ने जानकारी दी कि इस कार्य से वे सालाना लगभग एक लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकेंगी। इस पर अमित शाह ने बस्तर की इमली का स्वाद चखते हुए कहा कि यहां की इमली में खटास नहीं बल्कि मिठास है।

सेवा सेतु केंद्र में उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और सुविधाओं का जायजा लिया। ग्राम नेतानार की सुखदेवी ने बताया कि पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर दूर नानगुर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध हो गई है। केंद्र में आधार से जुड़ी सेवाएं, केवाईसी, मोबाइल अपडेट और विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा एक ही स्थान पर मिल रही है।

इसी केंद्र में सोनामनी ने बताया कि दूरी के कारण वे लंबे समय से महतारी वंदन योजना का केवाईसी नहीं करा पा रही थीं, लेकिन अब गांव में ही सुविधा मिलने से उन्होंने तुरंत प्रक्रिया पूरी कर ली। केंद्र में जन्म, आय, जाति प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं उपलब्ध हैं और महिलाओं को बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे बैंकिंग सेवाएं गांव में ही प्रदान कर सकेंगी। अमित शाह ने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र और धान डेकी प्रशिक्षण केंद्र का भी निरीक्षण किया। सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि इससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार का बेहतर पालन-पोषण कर पाएंगी। वहीं धान डेकी केंद्र के माध्यम से महिलाओं को चावल उत्पादन और उससे जुड़े संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आय बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

इमली से बढ़ रही महिलाओं की आय

नेतानार में स्व सहायता समूह की महिलाएं इमली का प्रसंस्करण कर उच्च गुणवत्ता वाला पल्प तैयार कर रही हैं। इस पहल से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है और उनकी सालाना आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। बस्तर की इमली अब आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है।

गांव तक पहुंची डिजिटल सुविधाएं

जन सुविधा केंद्र और सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से अब ग्रामीणों को आधार, केवाईसी, प्रमाण पत्र, बैंकिंग जैसी सेवाएं गांव में ही मिल रही हैं। पहले जहां लोगों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध होने से जीवन आसान हुआ है।